

visit us : krishichaupal.com

MAY 2021 • ₹20

कृषि चौपाल

कृषि एवं ग्रामीण विकास को समर्पित मासिक



ड्रैगन फ्रुट

खेती भी आसान
मुनाफा भी चौखा



14 वर्षों से अनवरत सेवा में...





कृषि चौपाल
कृषि एवं ग्रामीण विकास को समर्पित

वर्ष: 14 ❖ अंक: 2
मई 2021

संपादक
महेन्द्र सिंह बोरा

प्रसार प्रबंधक
दलीप जीना

डिजाइन
कल्पना प्रिंटोग्राफिक्स

संपादकीय कार्यालय
कृषि चौपाल

सी-355, तृतीय तल, गली नं. 9,
वेस्ट विनोद नगर, दिल्ली-110092

Phone: +91-9910406059

WhatsApp No.: 7505599489

Email: krishichaupal@gmail.com

Website: krishichaupal.com

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक
महेन्द्र सिंह बोरा द्वारा सी-355, तृतीय तल, गली
नं. 9, वेस्ट विनोद नगर, दिल्ली-110092 से
प्रकाशित और श्री इंटरप्राइजेज, डी-93, सैक्टर-7,
नौएडा, जनपद गौतम बुद्ध नगर,
उत्तर प्रदेश से मुद्रित।

'कृषि चौपाल' में प्रकाशित लेखों में व्यक्त किये गये
विचार लेखकों की अपनी अभिव्यक्तियाँ हैं। संपादकीय
मंडल का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। 'कृषि
चौपाल' में दिये गये विभिन्न उपचारों, सुझावों पर अमल
करने पर यदि किसी को किसी प्रकार की क्षति होती
है तो इसके लिए 'कृषि चौपाल' को जिम्मेदार नहीं
ठहराया जा सकता है। सुझाये गये विभिन्न उपचारों और
परामर्शों पर अमल करने से पूर्व संबंधित विशेषज्ञों की
राय को प्राथमिकता दें। किसी भी तरह के विवाद का
निपटारा दिल्ली/नई दिल्ली की सीमा में आने वाले सक्षम
न्यायालयों और फोरमों में ही किया जाएगा।

चित्र साभार: google.com

गांवों में कोरोना का कहर


आजकल देश के गांवों में कोरोना ने कहर बरपा रखा है। प्रकृति का
ऐसा रौद्र रूप किसी ने नहीं देखा होगा। कहते हैं 1918 से 1920 में
दो साल स्पैनिश फ्लू ने मौत का तांडव किया था। करीब 5 करोड़
लोग बेमौत मारे गये थे। प्रकृति ने कोहराम मचा दिया था। ठीक उसके 100 साल
बाद 2020 में एक नई महामारी कोरोना ने पूरी दुनिया की रूह कंपा दी है। लाखों
जानें यकायक लाश बन चुकी हैं। पूरा विश्व त्राहिमाम्-त्राहिमाम् पुकार रहा है। किसी
के पास इसका तोड़ नहीं हैं। वैस सब चीन की तरफ इशारा कर रहे हैं। कह रहे हैं
कि वुहान स्थित चाइना बायरोलॉजिकल लैब से वाइरस पूरी तैयारी के साथ मिशन
में निकाला गया है। अंदेशा है कि तीसरा विश्व युद्ध गोला-बारूद से नहीं बल्कि
जैविक हथियारों () से लड़ा जाएगा। मानव जाति अपनी बर्बादी को खुद ही न्यौता
दे रही है। मनुष्य के दिमाग ने इतना विकास कर लिया है कि उसके नशे से वह
बौरा गया है। अजीब मंजर है।

जो भी हो, कोरोना ने भारत में शहरों के बाद अब गांवों में कहर बरपा रखा है।
गंगा मझ्या भी रो रही है। यूपी-बिहार में गंगा किनारे कहीं-कहीं लाशें तैर रही हैं
तो कहीं सड़ रही हैं। जब ग्रामीणों की गुरबत में गाज गिर रही है तो वे गंगा के
आंचल का सहारा ढूँढ रहे हैं। उनके लिए गंगा जीवन भी है और मरण भी। इंसानी
मांस के सड़ने की बदबू आ रही है। लोगों का जीना दूभर हो गया है। सहमे पड़े हैं
कि कहीं मुसीबत के सिर पर आफत न बैठ जाए।

संघ प्रमुख मोहन भागवत जी का कहना भी सही है कि पिछले साल लॉकडाउन
के बाद हम सब गफलत में आ गये थे। जनता और सरकार दोनों लापरवाह हो गये
थे। जबकि चिकित्सा विज्ञानी कह रहे थे कि कोरोना लौटकर आएगा और पहले से
ज्यादा ताकतवर होकर वार करेगा, क्योंकि उसमें म्यूटेशन (स्वरूप परिवर्तन) हो रहा
है। उनकी बात सही थी। ऐसा ही होता है, रणभूमि में पराजित सेना जब लौटकर
जवाब देती है तो दोगुनी जान लगाती है। दूसरी लहर में कोरोना ने भी ऐसा ही
किया। यह महानगरों, नगरों, कस्बों से होता हुआ गांवों में घुस गया और चारों तरफ
हाहाकार मचा दिया।

जनता अपनी-अपनी सरकार को गरिया रही है। इटली, अमेरिका, ब्राजील, ब्रिटेन,
रूस, फ्रांस, आस्ट्रेलिया, जापान जैसे जब घुटने के बल आ गये तो भारत की क्या
बिसात है। 130 करोड़ की जनसंख्या का यह देश इन सारे यूरोपीय देशों को मिलाकर
भी इस मामले में सवा शेर है। यहां स्थिति दारुण है, वातावरण भयभीत है, फिर भी
जीने का हौसला बरकरार है।

बेशक प्रकृति रूठ गयी है। लेकिन हर रात की सुबह होती है। यह भी प्रकृति का
बनाया नियम है। ये बुरा दौर भी गुजर जाएगा। एक दिन नई भोर होगी। फिर सबकुछ
वैसा ही होगा, जैसा पहले था, उससे भी बेहतर।


महेन्द्र बोरा



गेहूं की खरीद में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 32 प्रतिशत वृद्धि

गेहूं की खरीद वर्तमान रबी विपणन सत्र आरएमएस 2021-22 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, जम्मू और कश्मीर तथा बिहार राज्यों में सुचारु रूप से जारी है और 12 मई 2021 तक 353.99 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। जबकि पिछले साल की इसी समान अवधि में 268.91 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया था। लगभग 36.19 लाख किसान मौजूदा एमएसपी मूल्यों पर हुए खरीद कार्यों से लाभान्वित हो चुके हैं और उन्हें 69,912.61 करोड़ रुपये का भुगतान उनके बैंक खातों के जरिए किया जा चुका है। 'वन नेशन, वन एमएसपी, वन डीबीटी' मिशन को पहली बार एक मजबूत रूप मिला है। अब देश भर में डीबीटी लागू कर दिया गया है।

वर्तमान खरीफ 2020-21 में धान की खरीद इसकी बिक्री वाले राज्यों में सुचारु रूप से जारी है। 12 मई 2021 तक 740.22 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान क्रय किया जा चुका है (इसमें खरीफ फसल का 705.45 लाख मीट्रिक टन और रबी फसल का 34.77 लाख मीट्रिक टन धान शामिल है), जबकि पिछले वर्ष की इसी समान अवधि में 684.66 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया था। मौजूदा खरीफ विपणन सत्र में लगभग 110.74 लाख किसानों को पहले ही एमएसपी मूल्य पर 1,39,755.10 करोड़ रुपये का भुगतान करके खरीद से लाभान्वित किया जा चुका है।

इसके अलावा, प्रदेशों से मिले प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश

जैसे राज्यों से खरीफ विपणन सत्र 2020-21 एवं रबी विपणन सत्र 2021 के लिए मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत 107.37 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद को भी मंजूरी प्रदान की गई थी। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों से 1.74 लाख मीट्रिक टन खोपरा (बारहमासी फसल) को क्रय करने के लिए भी स्वीकृति दी गई है। यदि अधिसूचित फसल अवधि के दौरान संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बाजार की दरें एमएसपी से नीचे चली जाती हैं, तो राज्य की नामित खरीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के अंतर्गत दलहन, तिलहन और खोपरा फसल की खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर भी मंजूरी दी जाएगी, ताकि पंजीकृत किसानों से वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित किये गए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सीधे इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद की जा सके।

खरीफ 2020-21 और रबी 2021 के तहत 12 मई 2021 तक सरकार द्वारा अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 6,59,584.98 मीट्रिक टन मूंग, उड़द, तुअर, चना, मसूर, मूंगफली, सरसों और सोयाबीन की खरीद एमएसपी मूल्यों पर की गई है। इस खरीद से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा और राजस्थान के 4,00,168 किसानों को 3,455.20 करोड़ रुपये की आय हुई है।

इसी तरह से 5,089 मीट्रिक टन खोपरा (बारहमासी फसल) की खरीद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से की गई है। इस दौरान 12 मई 2021 तक 3,961 किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 52 करोड़ 40 लाख रुपये की अदायगी की गई है।



कोरोना महामारी के बावजूद वैश्विक कृषि निर्यात में 18.49 प्रतिशत की बढ़त

पिछले वर्ष 2019-20 के दौरान भारत का कृषि एवं संबद्ध जिंसों का निर्यात 2.52 लाख करोड़ रुपये और आयात 1.47 लाख करोड़ रुपये का था। यहां तक कि महामारी के कठिन समय में भी भारत ने इस बात का ध्यान रखा कि वैश्विक खाद्य आपूर्ति श्रृंखला टूटने न पाए और लगातार निर्यात को जारी रखा। अप्रैल 2020 से फरवरी 2021 के दौरान कृषि एवं संबद्ध जिंसों का 2.74 लाख करोड़ रुपये का निर्यात किया गया जो पिछले साल की समान अवधि में हुए 2.31 लाख करोड़ रुपये के निर्यात के मुकाबले 18.49 प्रतिशत अधिक रहा।

निर्यात में महत्वपूर्ण सकारात्मक वृद्धि दर्शाने वाली वस्तुओं में गेहूं, अन्य अनाज, चावल, सोया मील, मसाले, चीनी, कपास, ताजा सब्जियां, प्रसंस्कृत सब्जियां और मादक पेय शामिल हैं।

गेहूं और अन्य अनाजों के मामले में पिछले साल की तुलना में भारी वृद्धि दर्ज हुई और ये क्रमशः 425 करोड़ रुपये से बढ़कर 3283 करोड़ रुपये और 1318 करोड़ रुपये से बढ़कर 4542 करोड़ रुपये हो गई। कुछ खास देशों की मांग पर नैफेड ने जी-टू-जी व्यवस्था के तहत 50,000 मीट्रिक टन गेहूं का निर्यात अफगानिस्तान को और 40,000 मीट्रिक टन गेहूं का निर्यात लेबनान को किया। भारत ने गेहूं के निर्यात के मामले में 727 प्रतिशत की जबरदस्त वृद्धि दर्ज की।

देश ने चावल (गैर बासमती) के निर्यात के मामले में भी 132 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की। गैर बासमती चावल का निर्यात 2019-20 के 13,030 करोड़ रुपये से बढ़कर 2020-21 में 30,277 करोड़ रुपये हो गया। निर्यात में यह वृद्धि कई कारकों की वजह से हुई जिनमें से मुख्य थी तिमोर-लेस्ते,

पपुआ न्यू गिनी, ब्राजील, चिली और प्यूटो रिको के बाजारों पर भारत का कब्जा होना। इन देशों के अलावा टोगो, सेनेगल, मलेशिया, मेडागास्कर, इराक, बांग्लादेश, मोजाम्बीक, वियतनाम तथा तंजानिया को भी चावल निर्यात किया गया।

भारत ने सोया मील का निर्यात भी बढ़ाकर 132 प्रतिशत कर दिया। सोया मील का निर्यात 2019-20 के 3087 करोड़ रुपये के मुकाबले 2020-21 में 7224 करोड़ रुपये हो गया।

कृषि एवं संबद्ध जिंसों के जिन अन्य उत्पादों के निर्यात में भी पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में अप्रैल 2020 से फरवरी 2021 के दौरान महत्वपूर्ण वृद्धि हुई, वे हैं - मसाले (23562 करोड़ रुपये की तुलना में 26257 करोड़ रुपये, 11.44% की वृद्धि), चीनी (12226 करोड़ रुपये की तुलना में 17072 करोड़ रुपये, 39.64% की वृद्धि), कपास (6771 करोड़ रुपये की तुलना में 11373 करोड़ रुपये, 67.96% की वृद्धि), ताजा सब्जियां (4067 करोड़ रुपये की तुलना में 4780 करोड़ रुपये, 17.54% की वृद्धि) और प्रसंस्कृत सब्जियां (1994 करोड़ रुपये की तुलना में 2846 करोड़ रुपये, 42.69% की वृद्धि) आदि।

कृषि एवं संबद्ध वस्तुओं का आयात अप्रैल 2020 से फरवरी 2021 के दौरान 141034.25 करोड़ रुपये रहा जो पिछले साल की इसी अवधि में 137014.39 करोड़ रुपये था, इसमें 2.93% की मामूली वृद्धि हुई।

कोविड-19 के बावजूद कृषि क्षेत्र का व्यापार संतुलन भी अप्रैल 2020 से फरवरी 2021 के दौरान पर्याप्त बढ़ा और पिछले साल की समान अवधि के 93,907.76 करोड़ रुपये के मुकाबले 132,579.69 करोड़ रुपये हो गया।

खाद्य तेलों के दाम जल्द घटने की उम्मीद



केन्द्र सरकार ने खाद्य तेलों के खुदरा दाम में जल्द नरमी की उम्मीद जताई है। सरकार का कहना है कि आयातित खाद्य तेलों की बड़ी खेप कई बंदरगाहों पर विभिन्न स्वीकृतियों के इंतजार में अटकी पड़ी है। बंदरगाहों से इस खेप के बाजार में आ जाने के बाद खाद्य तेलों के दाम में नरमी आयेगी।

पिछले एक वर्ष के दौरान खाद्य तेलों के दाम 55.55 फीसदी तक बढ़ गये हैं। कोरोना संकट की दूसरी लहर के चलते पहले से ही संकट में पड़े उपभोक्ताओं को खाद्य तेलों के दाम में यह बढ़ोतरी ज्यादा चिंतित कर रही है। आंकड़े बताते हैं कि इस वर्ष आठ मई को वनस्पति तेल का खुदरा मूल्य 140 रुपये प्रति किलो पर जा पहुंचा, जो पिछले वर्ष इसी

समय 90 रुपये प्रति किलो के स्तर पर था। वहीं पाम ऑयल का भाव पिछले एक वर्ष में 87.5 रुपये प्रति किलो से करीब 52 फीसद बढ़कर 132.6 रुपये प्रति किलो पर जा पहुंचा है। सोयाबीन तेल एक वर्ष पहले 105 रुपये प्रति किलो का मिल रहा था जो अब 158 रुपये प्रति किलो का मिल रहा है।

खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने कहा कि सरकार खाद्य तेलों के दाम पर हमेशा पैनी नजर रखती है। इस जरूरी आइटम के दाम में बढ़ोतरी पर काबू पाने के लिए सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है। उन्होंने बताया कि इस उद्योग द्वारा दी जानकारी के अनुसार खाद्य तेलों की बड़ी खेप कांडला और मुद्रा बंदरगाहों (दोनों गुजरात में) पर अटकी पड़ी है। इसकी मुख्य वजह यह है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए बंदरगाहों पर क्लियरेंस देने से पहले इनके कई जरूरी परीक्षण होने हैं, जो खाद्य वस्तुओं के लिए जरूरी मानकों में हैं।

खाद्य सचिव का कहना था कि सीमा शुल्क अधिकारियों और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों के साथ इस बारे में बात हुई है और बंदरगाहों पर पड़ी खेप को जल्द से जल्द से बाजार तक पहुंचाने की प्रक्रिया चल रही है। उनके मुताबिक खाद्य तेलों के मामले में देश काफी हद तक आयात पर निर्भर करता है। भारत सालाना लगभग 75,000 करोड़ रुपये मूल्य के खाद्य तेलों का आयात कर रहा है। (प्रेट)

दाल उत्पादन बढ़ाने पर जोर

खरीफ सीजन 2021-22 में 20 लाख से अधिक मिनी किट बांटने का लक्ष्य रखा गया है। यह संख्या पिछले वर्ष के मुकाबले 10 गुना अधिक है। इस पर तकरीबन 82 करोड़ रुपये से अधिक खर्च होंगे और इसे पूरा केन्द्र सरकार वहन करेगी। वितरित किये जाने वाले पैकेटों में सर्वाधिक 13.52 लाख पैकेट अरहर के हैं, जबकि लगभग पांच लाख पैकेट मूंग और पौने दो लाख पैकेट उड़द के होंगे। इस योजना की सफलता के लिए बीज वितरण के काम में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों के साथ जिले के कृषि विज्ञान केन्द्रों और राज्यों के कृषि विश्वविद्यालयों को लगाया गया है।

अरहर बीज के मिनी किट बांटने के लिए 11 राज्यों के 187 जिलों का चयन किया गया है। इनमें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य हैं। जबकि मूंग के बीजों का वितरण नौ राज्यों आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना के 85 जिलों में किया जाएगा। उड़द के लिए छह राज्यों आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के 60 जिलों में वितरण किया जाएगा।

अभी देश में दालों की मांग के अनुसार उत्पादन नहीं हो



पा रहा है और हर साल दालों के आयात में लगभग 15-20 हजार करोड़ रुपये खर्च करने पड़ते हैं। इसलिए खरीफ सीजन की प्रमुख दलहनी फसल अरहर (तूअर), मूंग और उड़द की उत्पादका बढ़ाने के लिए इन फसलों की बोआई का रकबा बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार का मानना है कि इससे दाल आयात की निर्भरता कम होगी और जो पैसा बचेगा उसे दलहनी फसलों की पैदावार बढ़ाने में खर्च किया जाएगा। इसलिए किसानों को दलहनी फसलों के उत्पादन के प्रति प्रेरित करने के लिए सरकार मुफ्त में बीज बांट रही है।



पीएम-किसान की आठवीं किस्त जारी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 14 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) के तहत 9,50,67,601 लाभार्थी किसानों को 2,06,67,75,66,000 रुपये के वित्तीय लाभ की 8वीं किस्त जारी की। इससे कोरोना से हलकान ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को सीधा लाभ मिला है। पहली बार पश्चिम बंगाल के किसानों को भी इस योजना का लाभ मिला है। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने किसान लाभार्थियों से बातचीत भी की। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री भी उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री ने पीएम-किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात की। उन्होंने अपने क्षेत्र के युवा किसानों को जैविक खेती और नई कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश स्थित उन्नाव के अरविन्द की सराहना की। इसके अलावा उन्होंने बड़े पैमाने पर जैविक खेती के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित कार निकोबार के पैट्रिक की भी सराहना की। वहीं उन्होंने अपने क्षेत्र के 170 से अधिक आदिवासी किसानों का मार्गदर्शन करने के लिए आंध्र प्रदेश स्थित अनंतपुर की एन वेन्नुरामा के प्रयासों की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने मेघालय के पहाड़ी इलाकों में मसालों जैसे अदरक पाउडर, हल्दी और दालचीनी आदि मसालों के उत्पादन के लिए मेघालय के रविस्टार की सराहना की। इसके अलावा उन्होंने जम्मू और कश्मीर स्थित श्रीनगर के खुर्शीद से भी बातचीत की, जो जैविक रूप से सब्जियों जैसे शिमला मिर्च, हरी मिर्च और खीरे की खेती करते हैं।

उन्होंने उन किसानों के प्रयासों की सराहना की जिन्होंने इस महामारी के दौरान कठिनाइयों के बीच खाद्यान्न और बागवानी में रिकॉर्ड उत्पादन किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार प्रत्येक साल एमएसपी पर खरीद के नए रिकॉर्ड भी बना रही है। उन्होंने आगे बताया कि अब तक पिछले साल की तुलना में इस साल एमएसपी पर लगभग 10 प्रतिशत अधिक गेहूं की खरीद की गई है। अब तक गेहूं की खरीद के लिए लगभग 58,000 करोड़ रुपये सीधे किसानों के खाते में पहुंचे हैं।

प्रधानमंत्री ने इस बात को रेखांकित किया कि सरकार खेती में नए समाधान और नए विकल्प प्रदान करने के लिए लगातार

प्रयास कर रही है। जैविक खेती को बढ़ावा देना भी इनमें से एक प्रयास है। जैविक खेती से अधिक लाभ पहुंचता है और अब युवा किसानों द्वारा पूरे देश में इसे अपनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब गंगा के दोनों किनारों पर और इसके 5 किलोमीटर के दायरे में जैविक खेती की जा रही है, जिससे गंगा साफ रहे।

प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि इस महामारी के दौरान किसान क्रेडिट कार्ड की समय सीमा बढ़ा दी गई है और किस्तों को अब 30 जून तक नवीनीकृत किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में 2 करोड़ से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं।

राज्यवार पीएम-किसान सम्मान निधि के लाभार्थी किसानों की संख्या और धनराशि इस प्रकार है-

State-UT Name	Number of farmers	Amount transferred (in Rs.)
ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS	15857	32642000
ANDHRA PRADESH	4301882	9437854000
ARUNACHAL PRADESH	91811	189014000
ASSAM	1246277	4048380000
BIHAR	7758514	15795196000
CHHATTISGARH	2460478	5174490000
DELHI	12226	25584000
GOA	8584	18302000
GUJARAT	5479600	11559276000
HARYANA	1729311	3561590000
HIMACHAL PRADESH	901777	1832414000
JAMMU AND KASHMIR	855835	1793784000
JHARKHAND	1388264	2861544000
KARNATAKA	5167535	10652594000
KERALA	3339880	6849242000
LADAKH	16535	33726000
MADHYA PRADESH	8095544	16753310000
MAHARASHTRA	9160108	18920402000
MANIPUR	282506	574982000
MEGHALAYA	8967	18078000
MIZORAM	85662	180476000
NAGALAND	174564	351162000
ODISHA	2590315	7204622000
PUDUCHERRY	10154	20360000
PUNJAB	1756246	3537126000
RAJASTHAN	6615374	14024320000
TAMIL NADU	3715536	7519080000
TELANGANA	3542673	7244320000
THE DADRA AND NAGAR HAVELI AND DAMA	9666	19986000
TRIPURA	208075	423616000
UTTAR PRADESH	22508275	51505252000
UTTARAKHAND	825615	1699022000
WEST BENGAL	703955	2815820000
Total	95067601	206677566000

आईएमपीसीएल ने 160 करोड़ रुपये के राजस्व को पार किया



आयुष मंत्रालय की सार्वजनिक क्षेत्र की निर्माण इकाई, इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईएमपीसीएल) ने अपने उत्पादों की बिक्री में एक शानदार वृद्धि दर्ज करते हुए वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 164.33 करोड़ रुपए का कारोबार (संभावित आंकड़ा) दर्ज किया है। कंपनी के इतिहास में यह अब तक की सर्वाधिक उपलब्धि है। पिछले वर्ष 2019-20 में कंपनी का राजस्व आंकड़ा केवल 97 करोड़ रुपए था। यह वृद्धि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर जनता द्वारा आयुष उत्पादों और सेवाओं को तेजी से अपनाने के रुझानों को प्रतिबिंबित करती है।

आईएमपीसीएल की उपलब्धि में एक और आयाम जोड़ते हुए, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने हाल ही में मार्च 2021 को 18 आयुर्वेदिक उत्पादों को डब्ल्यूएचओ-जीएमपी/सीओपीपी प्रमाणन के अधीन करने की सिफारिश की थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन निरीक्षण करने के पश्चात फार्मास्यूटिकल उत्पादों को प्रमाणपत्र प्रदान करता है। यह प्रमाणन आईएमपीसीएल के उत्पादों की गुणवत्ता का समर्थन है। यह वैश्विक स्तर पर गुणवत्तायुक्त औषधियों की निर्यात गतिविधियों को प्रारंभ करने के लिए आईएमपीसीएल की मदद करेगा।

आईएमपीसीएल देश में आयुष दवाओं के सबसे भरोसेमंद निर्माताओं में से एक है और यह अपनी औषधियों की प्रामाणिकता के लिए जानी जाती है। कोविड-19 महामारी के दौरान, संस्थान ने कम से कम समय में देश की जरूरतों को पूरा करने में सफलता हासिल की। यह देश में पहली ऐसी कंपनी है जिसने प्रतिरक्षातंत्र को मजबूत करने वाली दवाओं को मात्र 350 रुपये में प्रदान किया है। सबसे कम कीमतों वाली किटों में यह किट अब अमेजन पर भी उपलब्ध है। पिछले दो महीनों में लगभग 2 लाख ऐसी किट बेची गई हैं। वर्तमान में आईएमपीसीएल 656 क्लासिकल आयुर्वेदिक, 332 यूनानी और 71 ट्रेडमार्क युक्त आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण विभिन्न रोगों के लिए कर रहा है।

जल कृषकों और खरीदारों को जोड़गी इलेक्ट्रॉनिक मार्केटप्लेस ई-सांता

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केटप्लेस ई-सांता (<https://esanta.gov.in>) की शुरुआत की। यह जल कृषकों और खरीदारों को जोड़ने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। यह किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। इससे निर्यातक सीधे किसानों से गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की खरीद कर सकेंगे। ई-सांता टर्म वेबपोर्टल के लिए तैयार किया गया, जिसका अर्थ इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन फॉर ऑगमेंटिंग एनएसीएसए फार्मर्स ट्रेड इन एक्वाकल्चर है। यह नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल एक्वाकल्चर (एनएसीएसए) के तहत समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) की एक विस्तारित शाखा है। इस वेबसाइट को हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगू, बंगाली और ओडिया भाषाओं में लांच किया गया है।

ई-सांता बाजार विभाजन को समाप्त करने के लिए एक डिजिटल ब्रिज है। यह बिचौलियों को खत्म करके किसानों एवं खरीदारों के बीच एक वैकल्पिक विपणन उपकरण के रूप



में काम करेगा। यह किसानों और निर्यातकों के बीच नकदी रहित, संपर्क सहित और पेपरलेस इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड प्लेटफॉर्म प्रदान करके पारंपरिक जलीय कृषि में क्रांति लाएगा। ई-सांता वेबसाइट सामूहिक रूप से उत्पादों को खरीदने वाले, मछुआरों एवं मत्स्य उत्पादक संगठनों को एक साथ लाने का एक माध्यम बन सकता है।

पीएमजीकेवाई योजना के तहत गरीबों को दो महीने मिलेगा मुफ्त राशन



कोविड-19 हालात के मद्देनजर गरीब और जरूरतमंदों के सामने मौजूद मुश्किलों को दूर करने के लिए, भारत सरकार ने मई और जून, 2021 महीने के लिए पीएमजीकेवाई योजना की घोषणा की है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग में सचिव श्री सुधांशु पांडे ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना की घोषणा की।

इस योजना के अंतर्गत, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के दायरे में आने वाले लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को प्रति महीने प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न

मुफ्त आवंटन करने का फैसला किया है। यह आवंटन पूर्व में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएम-जीकेवाई) के समान व्यवस्था की तर्ज पर मई और जून, 2021 के लिए एनएफएसए खाद्यान्न का आवंटन किया जाएगा। इसके लिए भारतीय खाद्य निगम मई और जून, 2021 महीनों के लिए संबंधित राज्य/यूटी सरकारों को उनके नियमित एनएफएसए आवंटन के अलावा अतिरिक्त 80 एलएमटी खाद्यान्न उपलब्ध कराएगा, जिसके लिए एफसीआई पूरी तरह तैयार है और उसके पास राज्यों/यूटी में खाद्यान्नों का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है।

इस योजना के अंतर्गत, एनएफएसए के तहत आने वाली दोनों श्रेणियों अंत्योदय अन्न योजना (एवाई) और प्राथमिक परिवारों (पीएचएच) में शामिल लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को एनएफएसए के तहत उनकी नियमित पात्रता से इतर प्रति महीना प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न (चावल/गेहूं) का अतिरिक्त कोटा उपलब्ध कराया जाएगा।

इससे पहले 2020-21 के दौरान, भारत सरकार ने पीएमजीकेवाई-1 (अप्रैल-जून, 2020) और पीएमजीकेवाई-2 (जुलाई-नवंबर, 2020) की घोषणा की थी, जिसके तहत एफसीआई द्वारा संबंधित राज्य/ यूटी सरकारों को 104 एलएमटी गेहूं और 201 एलएमटी चावल यानी कुल 305 एलएमटी खाद्यान्नों की सफलतापूर्वक आपूर्ति की गई थी।

नई दिल्ली में चार नये ट्राइब्स इंडिया बिक्री केंद्र खोले गये

नई दिल्ली के प्रमुख स्थानों पर ट्राइब्स इंडिया के चार नये बिक्री केंद्र खोले गये हैं। जनजातीय शिल्पकारों और जनजातीय उत्पादों की मार्केटिंग के जरिए जनजातीय शिल्पकारों की आजीविका को प्रोत्साहित करने के लिए जारी पहल के अंतर्गत ट्राइफेड देश भर में अपना खुदरा कारोबार बढ़ा रहा है।

ये चार शोरूम भारत के सभी राज्यों से सर्वश्रेष्ठ प्रामाणिक जनजातीय हस्तशिल्प और परंपराओं जैसे महेश्वरी, पोचमपल्ली, चंदेरी, बाग प्रदर्शित करेंगे, और धातु की उत्कृष्ट कलाकृतियों के साथ ही प्राकृतिक, जैविक उत्पाद और वस्तुएं, वन धन इसेन्शाल और रोग प्रतिरोधकता वर्धक जैसे ऑर्गेनिक दालें, मसालें, हर्बल चाय भी पेश करेंगे।

इन विशाल स्टोरों में आकर्षक श्रेणियों में वर्गीकृत, टेक्सटाइल, साड़ी और दुपट्टे जैसे बाग प्रिंट, पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए परिधान, उत्कृष्ट जनजातीय आभूषण, धातु कलाकृति, लौह-उत्पाद, चित्रों से सजे मिट्टी के बर्तन और वन धन प्राकृतिक उत्पादों के लिए खास काउंटर बनाये गये हैं।



जनजातीय कल्याण के लिए देश की प्रमुख एजेंसी के रूप में ट्राइफेड समाज में पीछे छूटे जनजातीय लोगों के सशक्तिकरण के लिए पूरे देश उनके समाज के आर्थिक उत्थान को प्रोत्साहन देते हुए जनजातीय कला और हस्तशिल्प उत्पादों की खरीद ट्राइब्स इंडिया ब्रांड के अंतर्गत खुदरा बिक्री केंद्रों के जरिए करती है।

6 राज्यों के 100 गांवों में कृषि मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट के बीच एमओयू



डिजिटल एग्रीकल्चर की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की कल्पना अब मूर्तरूप ले रही है। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभालने के बाद से श्री मोदी ने खेती-किसानी में आधुनिक तकनीक के उपयोग पर बहुत बल दिया है, ताकि इसके माध्यम से किसानों को सुविधा हो और उनकी आमदनी बढ़ सके।

कसी कड़ी में फसलोपरांत प्रबंधन एवं वितरण सहित स्मार्ट एवं सुव्यवस्थित कृषि के लिए किसान इंटरफेस विकसित करने हेतु 6 राज्यों (उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान व आंध्र प्रदेश) के 10 जिलों में चयनित 100 गांवों में पायलेट प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट आगे आया है। इस प्रोजेक्ट के लिए माइक्रोसॉफ्ट अपने स्थानीय भागीदार

क्रॉपडेटा के साथ शामिल हुआ है। इस संबंध में कैबिनेट मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष अनंत माहेश्वरी तथा क्रॉपडेटा टेक्नोलॉजी प्रा.लि. के प्रबंध निदेशक सचिन सूरी की मौजूदगी में एमओयू का आदान-प्रदान किया गया। प्रोजेक्ट एक वर्ष के लिए है व एमओयू करने वाले दोनों पक्षकार अपनी स्वयं की लागत से इसका वहन करेंगे। इस प्रोजेक्ट से चयनित 100 गांवों में किसानों की बेहतरी के लिए विविध कार्य होंगे, जो उनकी आय बढ़ाएंगे। ये प्रोजेक्ट किसानों की आदान लागत को कम करेगा व खेती में आसानी सुनिश्चित करेगा। देश में वाइब्रेंट डिजिटल कृषि पारिस्थितिक प्रणाली बनाने के लिए अन्य सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के प्लेयरो के साथ इसी प्रकार के पायलेट प्रोजेक्ट शुरू करने का प्रस्ताव है।

सरकार का उद्देश्य असंगत सूचना की समस्या दूर करके किसानों की आय में वृद्धि करना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से कई नई पहल शुरू की गई हैं। इस संबंध में एक प्रमुख पहल राष्ट्रीय कृषक डेटाबेस पर आधारित कृषि-कोष बनाना है। सरकार देशभर से किसानों के भू-रिकॉर्डों को जोड़कर किसान डेटाबेस तैयार कर रही है। पीएम किसान, मृदा स्वास्थ्य कार्ड और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित सरकार के पास उपलब्ध आंकड़े समेकित कर लिए गए हैं व अन्य आंकड़ों को जोड़ने की प्रक्रिया जारी है। कृषि मंत्रालय की सभी योजनाओं में जो भी परिसंपत्तियां निर्मित होगी, उसकी जियो टैगिंग की जाएगी।

मजदूरों का सहारा बनी मनरेगा

कोरोना की वजह से पूरे देश में हाहाकार मचा है और लॉकडाउन की स्थिति है। ऐसे में श्रमिक अपने-अपने राज्यों को लौट गये हैं। पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, जैसे औद्योगिक राज्यों में भी लगभग कामधाम बंद है। तमाम बड़े शहरों में छोटे रेस्टोरेंट, ढाबा या खुदरा दुकानों में काम करने वाले या रिक्शा चलाने वाले श्रमिक भी अपने मूल राज्य को लौट गये हैं। इससे गांवों में मनरेगा के तहत काम मांगने वालों की बढ़ोतरी हो गयी है।

एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल पिछले अप्रैल के मुकाबले 92 फीसदी काम की मांग बढ़ी है। इस साल अप्रैल में मनरेगा के तहत 2.57 करोड़ परिवारों की तरफ से काम की मांग रही जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 1.34 करोड़ का था।

निश्चित तौर पर स्थिति भयावह है। यदि हालात नहीं सुधरे या इसी बीच कोरोना की तीसरी लहर आती है तो एक बड़ा वर्ग गंभीर आर्थिक संकट में आ जाएगा।

इस बार मेहरबान रहेगा मानसून

किसानों के लिए आगामी फसल वर्ष के शानदार होने की उम्मीद है। भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि मानसून एक जून को केरल पहुंच जाएगा। मानसूनी हवाएं बता रही हैं कि इस साल पूरे देश में झमाझम बारिश होगी।

कोरोना के इस आपदा काल में मानसून की यह अच्छी खबर है। इससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

अनुमानों के मुताबिक देश के 75 फीसदी हिस्से में जून से सितंबर के बीच 103 फीसद बारिश होगी। उत्तरी क्षेत्र के मैदानी भागों और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में पूरे सीजन में कम बारिश की आशंका है। जबकि पूर्वी राज्यों बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में औसत से अधिक बारिश होगी।

अच्छी बात यह भी है कि इस साल मानसून की विदाई भी देर से होने का अनुमान है। कुल मिलाकर मानसून पूरे देश में जमकर बरसेगा और फसलें खूब लहलहाएंगी।

प्रधानमंत्री द्वारा स्वामित्व योजना के तहत ई-प्रॉपर्टी कार्ड का वितरण



पंचायती राज दिवस का ये दिन ग्रामीण भारत के नवनिर्माण के संकल्पों को दोहराने का एक महत्वपूर्ण अवसर होता है। ये दिन हमारी ग्राम पंचायतों के योगदान और उनके असाधारण कामों को देखने, समझने और उनकी सराहना करने का भी दिन है।

— नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस (24 अप्रैल) के अवसर पर वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से देश के 4,09,945 ग्रामीण परिवारों को स्वामित्व योजना के अंतर्गत ई-प्रॉपर्टी कार्ड देकर उन्हें उनके मकान का मालिकाना हक प्रदान किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने स्वामित्व योजना को पूरे देश में लागू किए जाने का शुभारंभ भी किया। प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार विजेता पंचायतों के बैंक खाते में बटन दबाकर सीधे पुरस्कार की धनराशि भी अंतरित की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि कोविड-19 की इस प्रतिकूलता में कोई भी परिवार भूखा ना सोये, गरीब से गरीब का भी चूल्हा जले, ये भी हमारी जिम्मेदारी है।

प्रधानमंत्री ने स्वामित्व योजना में अब तक हुए कार्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि स्वामित्व योजना गांव और गरीब के आत्मविश्वास को, आपसी विश्वास को और विकास को नई गति देने वाली है। आज गांव और गरीब को उसके घर का कानूनी दस्तावेज देने वाली यह अहम योजना पूरे देश में लागू की गई है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पंचायतों की भूमिका को बढ़ाया जा रहा है, पंचायतों को नए अधिकार दिये जा रहे हैं। पंचायतों को डिजिटल बनाने के लिए हर गांव को फाइबर नेट से जोड़ने का काम भी तेजी से चल रहा है। आज हर घर को शुद्ध जल देने के लिए चल रही जल जीवन मिशन जैसी बड़ी योजना की जिम्मेदारी पंचायतों को ही सौंपी गई है। आज गांव में रोजगार से लेकर गरीब को पक्का घर देने तक का जो व्यापक अभियान केंद्र सरकार चला रही है, वह ग्राम पंचायतों के माध्यम से ही आगे बढ़ रहा है।

अब आयुर्वेद से होगी पशु चिकित्सा



पशु चिकित्सा विज्ञान में आयुर्वेद तथा इससे संबंधित विषयों को लागू करने के लिए 7 अप्रैल 2021 को मत्स्य पालन, पशुपालन तथा डेयरी मंत्रालय के पशुपालन तथा डेयरी विभाग और आयुष मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके तहत पशु चिकित्सा विज्ञान में औषधीय पौधों के माध्यम से गुणवत्ता संपन्न दवा के नए फॉर्मूलेशनों पर शोध सहित अनुसंधान तथा विकास को बढ़ावा मिलेगा।

मनुष्य के साथ-साथ पशुओं की चिकित्सा में भी आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का इतिहास सदियों पुराना है। अंग्रेजी दवाओं के बढ़ते प्रभाव के चलते इस प्राचीन इलाज को दरकिनार कर दिया गया। देर से ही सही सरकार अब इस बात को स्वीकार तो कर रही है कि आयुर्वेदिक चिकित्सा हमारी धरोहर है, जिसका संरक्षण और संवर्द्धन जरूरी है।

इस सहयोग से पशु स्वास्थ्य लाभ, पशुपालक समुदाय तथा समाज के लाभ के लिए पशु चिकित्सा क्षेत्र में आयुर्वेद के उपयोग के इस्तेमाल के लिए नियामक व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। इस सहयोग से प्रशिक्षण के माध्यम से संबंधित क्षेत्रों में क्षमता सृजन होगा, सतत आधार पर हर्बल दवाइयों के लिए बाजार तलाशने में मदद मिलेगी और कृषि, तथा औषधीय पौधों के संरक्षण के लिए सेवाएं मिलेंगी। इस सहयोग से हर्बल पशु चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम विकसित करने में मदद मिलेगी और डेयरी किसानों तथा अनाज उत्पादक किसानों में हर्बल औषधि के उपयोग तथा जड़ी-बूटी कृषि के बारे में जागरूकता आएगी।

वन धन विकास योजना से मिला जनजातीय नवउद्यमिता को व्यापक प्रोत्साहन



वन धन विकास योजना से जनजातीय नव उद्यमियों को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन और मदद मिल रही है। 18 महीनों से भी कम समय में 33,360 वन धन विकास केंद्र खोले गए हैं। प्रत्येक वन धन विकास केंद्र में 20 जनजातीय सदस्य होते हैं और 15 ऐसे केंद्रों से मिलकर वन धन विकास केंद्र का एक क्लस्टर बनता है। वन धन विकास केंद्रों के यह क्लस्टर 23 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में वन क्षेत्रों में रहने वाले लगभग 6,67,000 जनजातीय लोगों को बड़े पैमाने पर आजीविका के अवसर, उन्हें बाजार से जुड़ने के साथ-साथ उद्यमिता के अवसर उपलब्ध कराएंगे। वन धन विकास योजना से अब तक कम से कम 50,00,000 लोग लाभान्वित हुए हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत ट्राइफेड जनजातीय

लोगों के लिए रोजगार सृजन करने और उनकी आय में वृद्धि करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर रहा है जिसमें वन धन जनजातीय उद्यमिता एक महत्वपूर्ण प्रयास है, जिसके अंतर्गत एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया गया जिसका नाम है मैकेनिज्म फॉर मार्केटिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस (एमएफपी) यानि लघु वन उत्पादों के विपणन का एक तंत्र। इसे एमएफपी योजना के लिए वैल्यू चेन के विकास और न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से शुरू किया गया है। वन धन जनजातीय उद्यमिता भी इसी के समान एक विशेष योजना है जिसे मूल्य संवर्धन और वन धन केंद्र की स्थापना द्वारा छोटे-छोटे वन उत्पादों की ब्रांडिंग और उनके विपणन की सुविधा जनजातीय लोगों के लिए उपलब्ध कराई जाती है ताकि वनों में रहने वाली आबादी की आजीविका और जीवन शैली में सुधार हो सके।

इस अभियान की सबसे अच्छी ख़ूबी यह है कि इसने वनों को बाजार उपलब्ध कराया है। अनेक जनजातीय उद्यमी बाजार से जुड़ गए हैं। इसके अंतर्गत फ्रूट कैंडी (आंवला, अनन्नास, जंगली सेब, अदरक, अंजीर, इमली), जैम (अन्ननास, आंवला, आलू, बुखारा), जूस (अन्ननास, आंवला, जंगली सेब, आलू, बुखारा, लेटकू), मसाले (दालचीनी, हल्दी, अदरक), अचार (बांस, किंग चिली), प्रसंस्कृत गिलोय आदि वन उत्पादों को प्रसंस्कृत और उनकी पैकिंग कर उन्हें बाजारों तक पहुंचाया जाता है। साथ ही ऐसे उत्पादों को जतपड़मेपदकपण्ववउ के ऑनलाइन मंच और ट्राइब्स इंडिया के विपणन केंद्रों द्वारा भी बेचा जाता है।

छोटे किसानों से आधुनिक खेती कराएगी हरियाणा सरकार

हरियाणा सरकार अब छोटे किसानों को आधुनिक खेती करने के लिए प्रेरित करेगी और किसानों का मार्गदर्शन करने के लिए प्रत्येक गांव में 'किसान मित्र' तैनात किए जाएंगे। 'हरियाणा की बात' कार्यक्रम के जरिये लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि प्रदेश में ज्यादातर किसान छोटी जोत वाले हैं। उनके हित में प्रदेश सरकार बहुत जल्द राज्य में 'किसान मित्र' योजना लागू करने जा रही है।

खट्टर ने कहा कि छोटे किसान जागरूकता के अभाव में पारंपरिक तरीकों से ही खेती कर रहे हैं। ऐसे किसानों की मदद के लिए प्रत्येक गांव में किसान मित्रों को तैनात किया जाएगा। यह किसान मित्र प्रगतिशील किसान होंगे। यह किसान छोटी जोत वाले किसानों को न केवल वैकल्पिक कृषि के बारे

किसान मित्र योजना - हरियाणा

दो एकड़ या उससे कम भूमि वाले किसानों को मिलेगा लाभ

सरकार द्वारा संचालित की जा रही सभी कल्याणकारी योजनाओं का मिल सकेगा प्रत्यक्ष लाभ

में जानकारी देंगे बल्कि आधुनिक, बीज, फसल की बुआई से लेकर कटाई तक आधुनिक तकनीक के बारे में बताएंगे।



लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन (एलएसी) योजना से बेहद आसान है जैविक प्रमाणीकरण

भारत सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार के कार निकोबार और द्वीपों के समूह नैनकोवरी के 14,491 हेक्टेयर क्षेत्र को जैविक प्रमाणपत्र दिया है। यह क्षेत्र पीजीएस-इंडिया (पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम) प्रमाणन कार्यक्रम के लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन (एलएसी) योजना के तहत जैविक प्रमाणीकरण से प्रमाणित किए जाने वाला पहला बड़ा क्षेत्र बन गया है।

कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग पारंपरिक जैविक क्षेत्रों की पहचान कर उन्हें प्रमाणित जैविक उत्पादन केन्द्र में बदलने पर काम कर रहा है। भारत सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार के कार निकोबार और द्वीपों के समूह नैनकोवरी के 14,491 हेक्टेयर क्षेत्र को जैविक प्रमाणपत्र दिया है। यह क्षेत्र पीजीएस-इंडिया (पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम) प्रमाणन कार्यक्रम के लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन (एलएसी) योजना के तहत जैविक प्रमाणीकरण से प्रमाणित किए जाने वाला पहला बड़ा क्षेत्र बन गया है।

कार निकोबार और द्वीपों के समूह नैनकोवरी पारंपरिक रूप से जैविक क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं। प्रशासन ने इन द्वीपों में जीएमओ बीज के किसी भी रासायनिक बिक्री, खरीद और उपयोग पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन ने स्थानीय समुदायों के सहयोग से भूमि स्वामित्व, काम करने के तरीके और बीते समय में अपनाई गई पद्धति को लेकर द्वीप और किसान के आधार पर डेटाबेस तैयार किया है। एक विशेषज्ञ समिति ने जैविक स्थिति का सत्यापन किया है और पीजीएस-इंडिया सर्टिफिकेट स्कीम के तहत क्षेत्र को जैविक प्रमाण देने की सिफारिश की है। इन रिपोर्टों के आधार पर भारत सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कार निकोबार और द्वीपों के समूह नैनकोवरी के 14,491 हेक्टेयर क्षेत्र को जैविक प्रमाण पत्र दिया है।

इन द्वीपों के अलावा हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर पूर्वी राज्यों और झारखंड और छत्तीसगढ़ के आदिवासी बेल्ट, राजस्थान के रेगिस्तानी जिले जैसे कृषि क्षेत्र हैं जो रासायनिक वस्तुओं के उपयोग से मुक्त हैं। ये क्षेत्र जैविक खेती के लिए प्रमाणित हो सकते हैं। कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग राज्यों के साथ मिलकर ऐसे क्षेत्रों की पहचान करने और उन्हें जैविक खेती के लिए उपयुक्त क्षेत्र के रूप में प्रमाणित करने का काम कर रहा है। इसके साथ ही ब्रांडिंग और लेबलिंग के माध्यम से उस क्षेत्र के विशिष्ट उत्पाद को पहचान कर मार्केटिंग के जरिये बाजार दिलाने की कोशिश भी कर रहा है।

इसके अलावा अलग-अलग किसानों को प्रमाणित जैविक श्रेणी में लाने के लिए पीकेवीवाई (परंपरागत कृषि विकास योजना) के तहत एक जैविक प्रमाणीकरण सहायता योजना शुरू की गयी है। इस योजना के तहत व्यक्तिगत किसान एनपीओपी या पीजीएस-इंडिया के किसी भी प्रचलित प्रमाणन प्रणाली के तहत प्रमाणीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। राज्यों के माध्यम से प्रमाणन एजेंसियों को सीधे प्रमाणन लागत के भुगतान के रूप में सहायता उपलब्ध होगी।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बाद लक्षद्वीप और लद्दाख अपने पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को प्रमाणित जैविक क्षेत्र में बदलने के लिए लगातार कदम उठा रहे हैं। सर्टिफिकेशन के बाद इन क्षेत्रों की जैविक खाद्य बाजार तक सीधी पहुंच होगी।



- कृषि मंत्रालय पारंपरिक जैविक क्षेत्रों की पहचान कर उन्हें प्रमाणित जैविक उत्पादन केन्द्र में बदलने का काम कर रहा है।
- पहले चरण में केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार के 14,491 हेक्टेयर एरिया को 'लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन' स्कीम के तहत जैविक प्रमाणीकरण से नवाजा गया।
- 'लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन' जैविक प्रमाणीकरण की सरल, किफायती और अल्प समय लेने वाली प्रक्रिया है। इसमें किसानों को जैविक अर्हता प्राप्त करने के लिए 2-3 साल की अवधि का इंतजार नहीं करना पड़ता।
- जैविक प्रमाणपत्र मिलने से क्षेत्र विशेष की सीधी पहुंच देश के उभरते जैविक खाद्य बाजार तक होगी



जैविक खेती की पृष्ठभूमि

जैविक खेती की पहचान एक बड़ी जीवन शक्ति विकल्प के रूप में की गई है जो सुरक्षित और रासायनिक अवशेष मुक्त भोजन और खाद्य उत्पादन प्रणालियों को लंबे समय तक स्थिरता प्रदान करती है। कोविड-19 महामारी ने जैविक उत्पाद की आवश्यकता और मांग को और बढ़ा दिया है। विश्व में जैविक खाद्य की मांग बढ़ रही है और भारत इसका अपवाद नहीं है। 2014 के बाद से रसायन मुक्त खेती के पर्यावरण और मानव लाभ के महत्व को समझते हुए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार परंपरागत कृषि विकास योजना, उत्तर पूर्व में जैविक मिशन आदि की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जैविक/प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। भारत में अब 30 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र जैविक प्रमाणीकरण के तहत पंजीकृत है और धीरे-धीरे अधिक से अधिक किसान इस मुहिम में शामिल हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण रिपोर्ट (2021) के अनुसार, भारत क्षेत्रफल के मामले में 5वें स्थान पर है और कुल उत्पादकों की संख्या (आधार वर्ष 2019) के मामले में शीर्ष पर है।

लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन के माध्यम से जैविक खेती के लिए पारंपरिक कृषि क्षेत्र की पहचान

आधुनिक कृषि पद्धतियों का विस्तार बड़े क्षेत्रों में होने के बावजूद भारत में अभी भी पहाड़ियों, जनजातीय जिलों, रेगिस्तान और वर्षा वाले क्षेत्रों में बड़े क्षेत्र हैं जो रासायनिक खाद्य के उपयोग से मुक्त हैं। इनमें थोड़े प्रयासों से ऐसे पारंपरिक/कार्बनिक क्षेत्रों को बिना किसी मेहनत के तुरंत ही जैविक प्रमाणीकरण के तहत लाया जा सकता है। कृषि और किसान कल्याण विभाग ने अपनी प्रमुख योजना परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के तहत इन संभावित क्षेत्रों का इस्तेमाल करने के लिए एक अनूठा त्वरित प्रमाणन कार्यक्रम 'लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन' (एलएसी) शुरू किया है।

जैविक उत्पादन के मानक नियम के तहत, रासायनिक इस्तेमाल वाले क्षेत्रों को जैविक के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 2-3 वर्षों का समय लगता है। इस अवधि के दौरान किसानों को मानक जैविक कृषि मानकों को अपनाने और प्रमाणन प्रक्रिया के तहत अपने खेतों का रख-रखाव करना होता है। सफलतापूर्वक समापन होने पर ऐसे खेतों को 2-3 वर्षों के बाद जैविक के रूप में प्रमाणित किया जा सकता है। प्रमाणन प्रक्रिया को प्रमाणीकरण अधिकारियों द्वारा विस्तृत डॉक्यूमेंटेशन और समय-समय पर सत्यापन की भी आवश्यकता होती है जबकि एलएसी के तहत आवश्यकताएं सरल हैं और क्षेत्र को लगभग तुरंत प्रमाणित किया जा सकता है। एलएसी एक त्वरित प्रमाणन प्रक्रिया है जो कम लागत वाली है और किसानों को पीजीएस जैविक प्रमाणित उत्पादों के विपणन के लिए 2-3 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ता है।

एलएसी के तहत, क्षेत्र के प्रत्येक गांव को एक क्लस्टर/ग्रुप के रूप में माना जाता है। गांव के अधार पर दस्तावेज सरल बनाए गए हैं। अपने खेत और पशुधन वाले सभी किसानों को मानक आवश्यकताओं का पालन करना होता है और प्रमाणित होने के बाद उन्हें संक्रमण अवधि तक इंतजार नहीं करना होता है। पीजीएस-इंडिया के अनुसार मूल्यांकन की एक प्रक्रिया द्वारा वार्षिक सत्यापन के माध्यम से वार्षिक आधार पर प्रमाणन का नवीनीकरण किया जाता है। ●



कोटा के किसान ने आम की ऐसी किस्म विकसित की जिसमें बारहों महीने आते हैं फल

आम की इस नई किस्म का विकास करने वाले गरीब किसान श्रीकृष्ण सुमन ने कक्षा दो तक पढ़ाई करने के बाद स्कूल छोड़ दिया था और अपना पारिवारिक पेशा माली का काम शुरू कर दिया था। 15 सालों की मेहनत और लगन से उन्होंने कलम से आम का एक ऐसा पौधा विकसित करने में सफलता हासिल की जो सदाबहार रहता है अर्थात् साल के बारहों महीने फल देता है।

उनके इस अनुसंधान को देखकर बड़े-बड़े कृषि विज्ञानी भी हैरत में हैं।

राजस्थान के कोटा निवासी किसान श्रीकृष्ण सुमन (55 वर्ष) ने आम की एक ऐसी नई किस्म विकसित की है जिसमें नियमित तौर पर पूरे साल सदाबहार नाम का आम पैदा होता है। आम की यह किस्म आम के फसल में होने वाली ज्यादातर प्रमुख बीमारियों और आम तौर पर होने वाली गड़बड़ियों से मुक्त है।

इसका फल स्वाद में ज्यादा मीठा और लंगड़ा आम जैसा होता है। नाटा पेड़ होने के चलते किचन गार्डन में लगाने के लिए उपयुक्त है। इसका पेड़ काफी घना होता है और इसे कुछ साल तक गमले में भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा इसका गूदा गहरे नारंगी रंग का और स्वाद में मीठा होता है। इसके गूदे में बहुत कम फाइबर होता है जो इसे अन्य किस्मों से अलग करता है। पोषक तत्वों से भरपूर आम स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा माना जाता है।

आम की इस नई किस्म का विकास करने वाले गरीब किसान श्रीकृष्ण ने कक्षा दो तक पढ़ाई करने के बाद स्कूल छोड़ दिया था और अपना पारिवारिक पेशा माली का काम शुरू कर दिया था। उनकी दिलचस्पी फूलों और फलों के बागान के प्रबंधन करने में थी जबकि उनका परिवार सिर्फ गेहूं और धान की खेती करता था। उन्होंने यह जान लिया था कि गेहूं और धान की अच्छी फसल लेने के लिए कुछ बाहरी तत्वों जैसे बारिश, पशुओं के हमले से रोकथाम और इसी तरह की चीजों पर निर्भर रहना होगा और इससे सीमित लाभ ही मिलेगा।

उन्होंने परिवार की आमदनी बढ़ाने के लिए फूलों की खेती शुरू की। सबसे पहले उन्होंने विभिन्न किस्म के गुलाबों की खेती की और उन्हें बाजार में बेचा। इसके साथ ही उन्होंने आम के पेड़ लगाने भी शुरू किये।

सन् 2000 में उन्होंने अपने बागान में आम के एक ऐसे



पेड़ को देखा जिसके बढ़ने की दर बहुत तेज थी, जिसकी पत्तियां गहरे हरे रंग की थीं। उन्होंने देखा कि इस पेड़ में पूरे साल बौर आते हैं। यह देखने के बाद उन्होंने आम के पेड़ की पांच कलमें तैयार कीं। इस किस्म को विकसित करने में उन्हें करीब 15 साल का समय लगा और इस बीच उन्होंने कलम से बने इन पौधों का संरक्षण और विकास किया। उन्होंने पाया कि कलम लगाने के बाद पेड़ में दूसरे ही साल से फल लगने शुरू हो गये हैं।



इस नई किस्म को नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन (एनआईएफ) इंडिया ने भी मान्यता दी। एनआईएफ भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्तसाशी संस्थान है। एनआईएफ ने आईसीएआर- राष्ट्रीय बागवानी संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चरल रिसर्च (आईआईएचआर), बैंगलौर को भी इस किस्म का स्थल पर जाकर मूल्यांकन करने की सुविधा दी। इसके अलावा राजस्थान के जयपुर के

जोबनर स्थित एस्कोएन एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ने इसकी फील्ड टेस्टिंग भी की। अब इस किस्म को पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम तथा आईसीएआर- नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सज (एनवीपीजीआर) नई दिल्ली के तहत पंजीकरण कराने की प्रक्रिया चल रही है। एनआईएफ ने नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन में इस सदाबहार आम की किस्म का पौधा कराने में भी सहायता की है। इस सदाबहार किस्म के आम का विकास करने के लिए श्रीकृष्ण सुमन को एनआईएफ का नौवां राष्ट्रीय तृणमूल नवप्रवर्तन एवं विशिष्ट पारंपरिक ज्ञान पुरस्कार (नेशनल ग्रासरूट इनोवेशन एंड ट्रेडिशनल नॉलेज अवार्ड) दिया गया है और इसे कई अन्य मंचों पर भी मान्यता दी गई है। अलग-अलग चैनलों के माध्यमों से एनआईएफ किसानों, किसान नेटवर्कों, सरकारी संगठनों, राज्यों के कृषि विभागों और स्वयंसेवी संगठनों तक आम की इस नई किस्म के बारे में जानकारी पहुंचाने का प्रयास कर रहा है।

श्रीकृष्ण सुमन को 2017 से 2020 तक देश भर से और अन्य देशों से भी सदाबहार आम के पौधों के 8000 से ज्यादा ऑर्डर मिल चुके हैं। वह 2018 से 2020 तक आंध्र प्रदेश, गोवा, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और चंडीगढ़ को 6000 से ज्यादा पौधों की आपूर्ति कर चुके हैं। 500 से ज्यादा पौधे राजस्थान और मध्य प्रदेश के कृषि विज्ञान केंद्रों और अनुसंधान संस्थानों में वे खुद लगा चुके हैं। इसके अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के विभिन्न अनुसंधान संस्थानों को भी 400 से ज्यादा कलमें भेज चुके हैं। ●

खेत में हाजिरी ही किसान की आमदनी को कर सकती है दोगुनी, तिगुनी और चौगुनी : किसान कपिल भाटिया



हिसार चंडीगढ़ रोड पर सूरवाला मोड़ के नजदीक वाकिंग डिस्टेंस पर बोर्ड दिखाई दे जाता है वी.डी. फार्म फ्रेश और वी.डी. ऑर्गेनिक्स। यहां आपको मिल जायेंगे किसान कपिल भाटिया जी, जो कहते हैं कि मैं अपना फार्म कभी भी छोड़कर कहीं नहीं जाता हूं, जब तक बहुत ही ज्यादा जरूरी ना हो। मेरी दादी जी का नाम श्रीमती बिशन देवी था और मेरा उनसे बड़ा लगाव था। मैंने 37 वर्ष की उम्र में जब खेती करनी शुरू की तो मैंने अपनी दादी जी के नाम से फार्म का नाम रखा। मैंने अपने गांव प्रभुवाला में खेती की शुरूआत करने से पहले प्राइवेट नौकरियां, अपना बिजनेस आदि सबकुछ करके देखा लेकिन मुझे कभी सुकून नहीं मिला। फिर जीवन में एक ऐसा मोड़ आया कि मैंने बैठकर सोचा तो महसूस किया कि नौकरी और बिजनेस से मैंने प्रबंधन के जो गुर सीखे हैं उन्हें यदि मैं अपने खेत में लागू कर दूं तो कुछ चमत्कार किया जा सकता है।

इसके बाद मैंने अपना पूरा समय खेत को देना शुरू किया तो मुझे महसूस हुआ कि यहां तो काम ही काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। हरेक स्टेप पर जो खर्चा हमारे सर बंधा हुआ है उसे हम युक्तिपूर्ण तरीके से न्यूट्रल करके उसे आमदनी के सोर्स के रूप में बदल सकते हैं।

हमारे पास पशुओं का गोबर डालने की व्यवस्था अच्छी नहीं थी, उसके लिए हमें बहुत दुखी होना पड़ता था। मैंने गोबर से वर्मी कम्पोस्ट बनाना शुरू किया और अपने खेत में प्रयोग किया तो नतीजे बेहतरीन निकले। फिर हमारे खेत का पूरा पाड़ने के बाद जो वर्मी कम्पोस्ट बच गया उसे बेचने के लिए मैंने ऑनलाइन बाजार का रुख किया और अमेजन डॉट

सफल किसान कपिल भाटिया का कहना है कि इधर-उधर की छोड़ पूरा समय अपनी खेती को दीजिये। फिर देखिये, इज्जत, दौलत और शोहरत आपके कदमों में होगी।

कॉम पर अपनी फर्म बनाकर रजिस्टर्ड की और अपना खेत का बनाया हुआ वर्मी कम्पोस्ट ऑनलाइन बेचना शुरू किया

बिना मिलावट का शुद्ध वर्मी कम्पोस्ट था तो मुझे बेहतरीन रिव्यू मिलने शुरू हुए और मेरा कारोबार और अधिक चमका। मैंने खर्चे को आमदनी में बदल लिया। फिर उसके बाद मैंने फलों-सब्जियों की खेती में हाथ आजमाया और यहां भी मंडी के चक्कर काटने की बजाए खुद अपना रिटेल स्टोर खोला जो अब धीरे-धीरे चलता-चलता अच्छा चल चुका है।

हिसार चंडीगढ़ राजमार्ग पर मेरा रिटेल आउटलेट होने की वजह से आते-जाते हुए काफी ग्राहक निरंतर रूप से मेरे फार्म के ताजे फल-सब्जियां लेकर जाते हैं। मैं अपनी खेती और खुद के रिटेल से बेहद संतुष्ट हूं और खुश हूं। मेरी जमीन भट्टे की जमीन है। यहां पानी-बिजली की सुविधा भी पर्याप्त नहीं है। जब मैंने काम शुरू किया था तो इस जमीन में कपास और बाजरा भी नहीं उगता था लेकिन आज धीरे-धीरे सुधार करते करते मैं अपनी खेती को इस स्तर पर ले आया हूं कि बीस खेतिहर मजदूरों के परिवार मेरे खेत से ही अपना ठीकठाक गुजारा कर रहे हैं। मेरे खेतों पर साल भर का काम रहता है। उनको काम के लिए कहीं नहीं भटकना पड़ता और मेरे काम की प्लानिंग ठीक होती है जिसकी वजह से मजदूरों का समय और मेहनत भी बर्बाद नहीं होता है।

पिछले पांच सालों में मैंने अपने जन संपर्क से अच्छी-खासी पहचान बना ली है और मुझे मेरी फसल के एडवांस ऑर्डर भी मिलने शुरू हो गये हैं जिससे मेरी पूरी टीम के हौसले एकदम टाइट हैं। आज सरकार किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात कर रही है, लेकिन मेरा अनुभव यह कहता है कि किसान सरकारों के पीछे भागना छोड़कर अपने आपको खेत में केंद्रित कर लें और अपने आसपास मौजूद बाजार में अकेला या संयुक्त रूप से घुसने का प्रयास करें तो उसकी आमदनी तिगुनी-चौगुनी तक हो सकती है।

किसान को हर रोज कौश कमाने की आदत डालनी चाहिए, तभी वह अपने फार्म को आर्थिक रूप से सबल बना पायेगा। मैं अपने अनुभव से आज यह कह सकता हूं कि खेती से बेहतरीन कोई धंधा नहीं है। यह रोजगार होने के साथ-साथ एक जीवन शैली भी है। इसलिए अपनी खेती को समय दीजिये, फिर देखिये, धन, मान-सम्मान और पहचान की कोई कमी नहीं रहेगी।

Courtesy : <https://hindi.indiawaterportal.org>



एक्वापोनिक्स: पानी की अनोरवी खेती

■ हिमांशु भट्ट

भारत कृषि प्रधान देश है। देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है 'कृषि'। जब से दुनिया में सभ्यताओं का प्रारंभ हुआ तभी से खेती की जा रही है। खेती करने के लिए मिट्टी, धूप, पानी और खाद की जरूरत पड़ती है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें जमीन में पौधा या बीज बो दो, तो कुछ महीनों में वह लहलहाती फसल और सालों में बड़ा पेड़ बन जाता है, लेकिन अब सब्जियां मिट्टी में ही नहीं बल्कि 'पानी' में भी उग सकती हैं, वह भी मछलियों वाले पानी में। खेती की इस पद्धति को 'एक्वापोनिक्स' कहते हैं। पानी से उगने वाली इन सब्जियों में मिट्टी में उगने वाली सब्जियों के मुकाबले अधिक पोषक तत्व होते हैं और पानी भी कम लगता है। जो जल संरक्षण की दृष्टि से लाभदायक है।

दुनिया भर में आबादी तेजी से बढ़ती जा रही है। कई अनुमान लगाए जाते हैं कि 2050 तक भारत की जनसंख्या 160 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी, लेकिन धरती पर जमीन उतनी ही रहेगी। हो सकता है बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए खेती और वन भूमि कम हो जाए। ऐसे में बढ़ती आबादी का दबाव पानी सहित सभी प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ेगा। इन संसाधनों में सबसे ज्यादा प्रभावित जल होगा। जल संकट का असर इंसान की कई जरूरतों के साथ ही खेती पर भी पड़ेगा, इसका असर अभी से दिखने भी लगा है

- एक्वापोनिक्स तकनीक का प्रयोग मरुस्थल, लवणीय, रेतीली, बर्फीली किसी भी प्रकार की भूमि पर किया जा सकता है।
- एक्वापोनिक्स में साधारण खेती के मुकाबले 90 प्रतिशत कम पानी लगता है।
- भविष्य की जरूरत और इन समस्याओं के समाधान के लिए 'एक्वापोनिक्स' तकनीक सबसे फिट बैठती है।

और भारत जल संकट के सबसे भीषण दौर से गुजर रहा है। कई स्थानों पर सूखे से किसानों की फसल बर्बाद हो रही है, जबकि विभिन्न स्थानों पर पानी के अभाव में किसानों को खेती छोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है। देश के विभिन्न स्थानों में खेती की जिस पद्धति को अपनाया जा रहा है, उसमें अधिकांश किसान अधिक पैदावार के लिए कीटनाशकों का उपयोग करते हैं। इसने फसल और मिट्टी को जहरीला बना दिया है, जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों को जन्म दे रहे हैं। कीटनाशक धरती से जैव विविधता को भी समाप्त कर रहे हैं। क्योंकि कीटनाशकों का उपयोग कीट मारने के लिए किया जाता है। इन मरे हुए कीटों को विभिन्न पक्षी खाते हैं जिस कारण उनकी भी मौत हो रही है। कई प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी हैं, जिनमें चील भी शामिल हैं। इसलिए वर्तमान परिस्थितियों से सबक लेते हुए और भविष्य को ध्यान में रखते



हुए जैविक खेती अपनाते तथा जल संरक्षण पर जो दिया जा रहा है। भविष्य की जरूरत और इन समस्याओं के समाधान के लिए 'एक्वापोनिक्स' तकनीक सबसे फिट बैठती है।

बेंगलुरु का माध्वी फार्म भारत का पहला और सबसे बड़ा एक्वापोनिक्स फार्म है, तो वहीं देश के विभिन्न स्थानों पर एक्वापोनिक्स खेती की जा रही है। इस तकनीक में पानी के टैंक या छोटे तालाब बनाए जाते हैं, जिनमें मछलियों को रखा जाता है। मछलियों के मल से पानी में अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है। इस पानी को पौधों के टैंक में डाल दिया जाता है। पौधे के टैंक में मिट्टी की जगह प्राकृतिक फिल्टर बनाया गया होता है, जहां पौधे पानी से आवश्यक पोषक तत्व सोख लेते हैं। फिर पानी को वापस मछलियों के टैंक में डाल दिया जाता है। इस प्रकार ये साइकिल रिपीट होता रहता है और जल की बर्बादी नहीं होती। एक्वापोनिक्स तकनीक का प्रयोग मरुस्थल,

लवणीय, रेतीली, बर्फीली किसी भी प्रकार की भूमि पर किया जा सकता है। इससे देश में लाखों हेक्टेयर बंजर भूमि का उपयोग किया जा सकता है। इससे आजीविका के साधन बढ़ेंगे तो वहीं एक्वापोनिक्स में साधारण खेती के मुकाबले 90 प्रतिशत कम पानी लगता है। यह मिट्टी पर उगने वाली फसल के मुकाबले तीन गुना तेजी से बढ़ती है। प्रति स्क्वायर फीट में अधिक पैदावार होती है। मिट्टी के मुकाबले इस तकनीक से उगी फसल में 40 प्रतिशत तक अधिक पोषक तत्व होते हैं और यह पूरी तरह जैविक होती है। इसके अलावा मछलियों को उपयोग भी उपभोग और आय के सृजन के लिए किया जा सकता है।

एक्वापोनिक्स तकनीक भविष्य को ध्यान में रखते हुए लाभदायक है, लेकिन इसमें मृदा उत्पादन और हाइड्रोपोनिक्स की तुलना में शुरुआती लागत अधिक आती है। मछलियों, बैक्टीरिया और पौधों की जानकारी होना बेहद जरूरी है। इस तकनीक के अंतर्गत पौधे उगाने के लिए अनुकूल तापमान की जरूरत होती है। हालांकि पूरे एहतियात और जानकारी प्राप्त कर यह खेती की जाती है, तो काफी लाभदायक है। जल संरक्षण की दृष्टि से तो काफी लाभदायक है। क्योंकि भारत भूजल का सबसे ज्यादा उपयोग खेती के लिए करता है या कहें कि सबसे ज्यादा पानी की बर्बादी खेती में ही की जाती है। इसलिए वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से हम कह सकते हैं कि एक्वापोनिक्स भविष्य की जरूरत है।

Courtesy : <https://hindi.indiawaterportal.org>

एनएफएल ने 59.36 लाख मी. टन की सर्वाधिक उर्वरक बिक्री की



एनएफएल ने एक बार फिर अब तक की सर्वाधिक उर्वरक बिक्री दर्ज की है जो 2020-21 में 59.36 लाख मीट्रिक टन रही है। यह 2019-20 के दौरान किये गये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 57.04 लाख मीट्रिक टन से भी बेहतर प्रदर्शन है। इसमें कंपनी ने अपने यूरिया, आयातित यूरिया और अन्य पी एंड के उर्वरकों की बिक्री भी शामिल है।

उत्पादन के मोर्चे पर कंपनी ने कोविड-19 के दौरान कड़े

प्रतिबंधों के बावजूद अपनी इकाइयों में अपनी क्षमता के 117.6 प्रतिशत का रिकॉर्ड उपयोग करते हुए 37.99 लाख मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन किया। इन इकाइयों में पानीपत इकाई ने यूरिया और बेंटोनाइट सल्फर के उत्पादन का एक नया रिकॉर्ड कायम किया और विजयपुर इकाई ने जैव-उर्वरकों की सर्वाधिक मात्रा का उत्पादन किया।

उर्वरकों के अलावा कंपनी ने बीजों और कृषि रसायनों की बिक्री में भी तीव्र वृद्धि दर्ज की है। बीजों की बिक्री में पिछले वर्ष की इस अवधि की तुलना में 35 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और यह 1,85,550 क्विंटल हो गयी, जबकि कृषि रसायनों के क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में 95 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यहां तक कि बेंटोनाइट सल्फर की जो एनएफएल की पानीपत इकाई में उत्पादित होता है, में भी 150 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह पिछले वर्ष की इसी अवधि की 7,974 मीट्रिक टन की तुलना में इस साल 19,958 मीट्रिक टन हो गयी। कंपनी ने 2020-21 के दौरान अपने औद्योगिक उत्पादों के कारोबार में भी उत्तम प्रदर्शन किया है।



(क) सिंचित अवस्था के लिए सुगंधित एवं बासमती धान की किस्में

किस्म	अनुमोदित क्षेत्र/परिस्थिति	उपज (क्विं/हे.)	विशेषताएं
पूसा बासमती-6 (पूसा 1401)	देश के बासमती धान उगाने वाले समस्त क्षेत्र/सिंचित अवस्था में बुआई के लिए	55-60	धान की यह मध्यम बौनी किस्म है जो पकने पर गिरती नहीं है। दानों की समानता व पकाने की गुणवत्ता के हिसाब से यह किस्म पूसा बासमती 1121 से बहुत ही अच्छी है, क्योंकि इसका दाना पकाने पर एक समान रहता है। इसमें बहुत अच्छी सुगंध आती है तथा दूधिया दानों की संख्या 4 प्रतिशत से कम है।
उन्नत पूसा बासमती-1 (पूसा 1460)	देश के बासमती धान उगाने वाले समस्त क्षेत्र/सिंचित अवस्था में बुआई के लिए	50-55	यह अधिक उत्पादन देने वाली झुलसा रोग प्रतिरोधी प्रजाति है। यह किस्म 135 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। पकाने में इसके दानों की गुणवत्ता बहुत अच्छी है और दूधिया दानों की संख्या 10 प्रतिशत से कम पाई गई है।
पूसा बासमती-1121	बासमती धान उगाने वाले समस्त क्षेत्र/सिंचित अवस्था में खेती के लिए	40	बासमती धान की यह किस्म 140-145 दिनों में पक जाती है जो तरावड़ी बासमती से एक पखवाड़ा अगेती है। इसका दाना लम्बा (8.0 मि.मी.) व पतला है जो गुणों में तरावड़ी बासमती से अच्छा है। यह कम लागत में उच्च गुणवत्ता युक्त निर्यात योग्य अधिक उपज देने वाली किस्म है।
पूसा सुगंध-5 (पूसा 2511)	पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर/सिंचित अवस्था में खेती के लिए	60-70	इस किस्म का दाना अच्छी सुगंध वाला एवं अधिक लंबा होता है। यह किस्म झड़ने के प्रति सहिष्णु है। यह गाल मिज, भूरे धब्बे की प्रतिरोधी है तथा पत्ती लपेट व ब्लास्ट के प्रति मध्यम प्रतिरोधी है। यह किस्म 125 दिनों में पककर तैयार हो जाती है।
पूसा सुगंध-3	पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड/सिंचित अवस्था में खेती के लिए	60	यह धान की अर्ध बौनी, अधिक उपज देने वाली, बासमती गुणों से परिपूर्ण किस्म है। इसका दाना लंबा, बारीक और सुगंधित है जो पकाने पर लंबाई में दोगुना बढ़ता है तथा खाने में मुलायम और स्वाद में अच्छा है। यह किस्म पकने में मध्यम अगेती (125 दिन) होने की वजह से बहुफसलीय चक्र जैसे कि धान-सब्जी (पालक, मूली, आलू)-गेहूँ-मूंग के लिए उपयुक्त है।

पूसा सुगंध-2	पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड/सिंचित अवस्था में खेती के लिए	55	यह धान की अर्ध बौनी, अधिक उपज देने वाली, बासमती गुणों से परिपूर्ण किस्म है। इसका दाना लम्बा, बारीक और सुगंधित है जो पकाने पर लंबाई में दोगुना बढ़ता है तथा खाने में मुलायम और स्वाद में अच्छा है। यह किस्म पकने में मध्यम अगती (120 दिन) होने की वजह से बहुफसलीय चक्र के लिए उपयुक्त है।
संकर धान पूसा आर.एच.-10	पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड/सिंचित अवस्था में रोपाई के लिए	65	यह बासमती गुणों वाली धान की विश्व में प्रथम संकर किस्म है। इसका दाना अत्यधिक सुगंधित, लंबा, पतला है जो पकाने पर दोगुना बढ़ जाता है और अधिक स्वादिष्ट होता है। यह एक मध्यम बौनी, जल्दी पकने वाली (110-115 दिन) किस्म है, जिससे सिंचाई की बचत होती है। यह किस्म उत्तरी भारत में गेहूँ-धान फसल प्रणाली के लिए उपयुक्त है।
पूसा बासमती-1	उत्तर-पश्चिमी भारत के बासमती उगाने वाले क्षेत्र/सिंचित अवस्था में रोपाई के लिए	45	यह बासमती धान की एक मध्यम बौनी किस्म है। इसका दाना अत्यधिक लंबा तथा पकाने पर मुलायम व सुगंधित होता है। देश के बासमती चावल के निर्यात में लगभग 30 प्रतिशत योगदान इसी किस्म का है। यह किस्म उत्तरी भारत में गेहूँ-धान फसल प्रणाली के लिए उपयुक्त है।

(ख) सिंचित क्षेत्र के लिए धान की असुगंधित किस्में

पूसा-44	कर्नाटक, केरल, पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश/सिंचित अवस्था में खेती के लिए	40-45	यह बौनी किस्म 140-145 दिनों में पकाकर तैयार हो जाती है। इसके दाने लंबे, इकहरे तथा पारभासी होते हैं, जिनका छिलका आसानी से उतर जाता है तथा मिलीकरण के दौरान दाना कम टूटता है। यह किस्म मशीनों द्वारा कटाई के लिए अति उपयुक्त है।
पी.एन.आर.-546	हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल/सिंचित क्षेत्रों के लिए	50-55	यह धान की अच्छे दाने वाली किस्म है जो 110 दिनों में पककर तैयार हो जाती है।

(ग) वर्षा पोषित क्षेत्र एवं उपराऊं अवस्था के लिए धान की किस्में

पूसा-834	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं उत्तर प्रदेश/उपराऊं अवस्था के लिए	40-45	यह बौनी किस्म मध्यम से ऊंचाई वाली जमीन में सीधी बुवाई तथा रोपण पद्धति में भी अच्छी उपज देती है। पौध की ऊंचाई 90 सेंमी., दाने मध्यम, लंबे तथा खाने में स्वादिष्ट तथा मुलायम होते हैं। फसल 120-125 दिन में पककर तैयार हो जाती है।
पी.एन.आर.-381	उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा महाराष्ट्र/उपराऊं अवस्था के लिए	40-45	धान की यह मध्यम बौनी किस्म (90 सें.मी.) है। इसके दाने मध्यम लंबे तथा स्वादिष्ट हैं। फसल 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है।
जल्दी धान-13	उपराऊं अवस्था- उड़ीसा, बिहार, झारखण्ड एवं पश्चिम बंगाल। सिंचित- पश्चिम बंगाल, बिहार/सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए	उपराऊं 30 30 क्वि/हे. सिंचित-40 क्वि/हे.	यह मोटे दाने की जल्दी पकने वाली किस्म है जो 90-95 दिनों में पककर तैयार हो जाती है।





स्नो ट्राउट भारतीय पहाड़ों की स्वदेशी मछली

स्नो ट्राउट (साइजोथोरैक्स रिचार्डसोनी) शीतजल की एक प्रमुख स्वदेशी प्रजाति है। इसे असेला अथवा माउंटेन बारबल के नाम से भी जाना जाता है। इसका विस्तार भारत में समुद्र तल से 300-2810 मीटर की ऊंचाई में जम्मू-कश्मीर से उत्तराखंड, असम, सिक्किम, नागालैंड एवं भूटान तक है।

यह जल स्रोतों के तल में निवास करने वाली शाकाहारी मछली है। यह प्रजाति जल की विभिन्न तापीय सीमा को सहन कर सकती है, लेकिन 8 से 22 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान वाली बफीली नदियों एवं तालाबों को ज्यादा पसंद करती है। सामान्यतः असेला तीन वर्ष से अधिक समय में परिपक्व होती है। इन मछलियों का वर्ष में दो बार (फरवरी-मई तथा अगस्त-अक्टूबर) प्रजनन होता है। अगस्त-अक्टूबर के समय को बीत उत्पादन के लिए उपयुक्त समय माना जाता है। स्वच्छ जल, तलछट में कंकड़-पत्थर, बजरी आदि का पर्याप्त मात्रा में जमाव तथा 1.5 से 3 लीटर प्रति सेकेन्ड जल प्रवाह, 7.4-8.2 पीएच, 8-10 पीपीएम घुलित ऑक्सीजन की सघनता अंडजनन के लिए बेहतर प्राकृतिक वातावरण बनाती है।

परिपक्व नर मछली तुलनात्मक रूप से आकार में छोटी होती है तथा इनका पेट हल्का फूला हुआ होता है। पंख पीले और लाल रंग के तथा खुरदरे पैक्टोरल पंख नर की विशेष पहचान होते हैं।

मादा मछली की पहचान गुलाबी, मुलायम तथा अधिक फूले पेट से की जाती है। इसके पैक्टोरल पंख चिकने होते हैं। पूर्ण रूप से परिपक्व मादा को जब उदर भाग में हल्के से दबाया जाता है तो यह नारंगी रंग के चिपचिपे अंडे देती है। इसकी सामान्य अंड जनन क्षमता 16,270 से 18,340 अंडे प्रति किलो तक होती है।

प्रजनन के लिए 70-80 ग्राम से अधिक भार वाली मादा तथा 40-50 ग्राम से अधिक भार वाले नर मछली का चयन किया जाता है। अल्प प्रकाश की स्थिति में शुष्क निषेचन विधि

को अपनाया जाता है। मादा मछली को पैलविन फिन के पास से उदर गुहा तक धीरे-धीरे से हल्के से दबाया जाता है और अंडों के ऊपर उसके शुक्र रस को गिराया जाता है तथा इस बात का पूरा ध्यान दिया जाता है कि अंडे वाली तश्तरी में कहीं कोई रक्त, पानी या पेट की गंदगी न रह जाये। बेहतर निषेचन के लिए 3-4 नर के शुक्र रस का प्रयोग अकेली मादा मछली के अंडों के निषेचन हेतु प्रयुक्त किया जाता है।

अच्छी गुणवत्ता वाले अंडे एक समान आकार तथा पीले-नारंगी रंग के होते हैं। निकाले गये अंडों तथा शुक्र रस को लगातार आपस में मिश्रित करके तथा शुक्राणुओं को सक्रिय करने हेतु उसमें पानी मिलाया जाता है। फिर इन्हें साफ पानी से दो-तीन बार धोया जाता है।

इस प्रजाति के अंडों में 60-75 प्रतिशत निषेचन के साथ 35-60 प्रतिशत हैचिंग प्राप्त होती है। कुल मिलाकर निषेचित अंडों से लेकर स्विम-अप-फ्राई (तैरने वाले जीरा) स्तर तक 30-45 प्रतिशत तथा स्विम-अप-फ्राई से लेकर वयस्क जीरा (विकसित जीरा) स्तर तक 65-80 प्रतिशत तक उत्तरजीविता रहती है। अंडों की हैचिंग के लिए 17-21 डिग्री से.ग्रे. जल के तापमान पर 5-7 दिन का समय लगता है। अंडपीत बनने में 84-468 घंटे लगते हैं। इसके लार्वा को आंतरिक बहते हुए जल प्रवाही पोषण शाला के अंदर ट्रे में लगभग 60 दिनों तक 1000-2000 वर्ग मीटर में 3-4 लीटर प्रति मिनट वाली जल प्रवाही दर में पाला पोषा जाता है। पालन वाले रेसवे (तालाब) में वयस्क जीरा को 100-150 प्रति जीरा में सचयित कर 30-40 लीटर प्रति मिनट वाले जल प्रवाह दर में उनके शरीर के भार के 10 प्रतिशत खुराक देकर पाला जाता है।

यद्यपि इस मछली की वृद्धि दर कम है, किंतु पहाड़ों में इसकी मांग को देखते हुए इसका कृत्रिम प्रजनन कर पुनर्वास तथा संरक्षण अत्यंत आवश्यक है।

(स्रोत: भा.कृ.अ.प. शीतजल मात्स्यिकी अनुसंधान निदेशालय, भीमताल, नैनीताल)



अगेती फूलगोभी से कमाएं अधिक आय

भारत में फूलगोभी की खेती 452 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल में की जाती हैं और उत्पादन 8499 हजार मीट्रिक टन है। वैसे तो फूलगोभी शीतकाल की एक महत्वपूर्ण फसल है लेकिन अगेती किस्मों के विकसित होने से अब इसकी खेती गर्मी एवं वर्षा ऋतु में भी किसान करने लगे हैं। अगेती फसल की पैदावार तो थोड़ी कम होती है लेकिन अधिक बाजार भाव, कम फसल अवधि और मौजूदा फसल प्रणाली में उत्तम समावेश होने के कारण इसकी लोकप्रियता किसानों में निरंतर बढ़ती जा रही है।

फूल बनने के लिए तापमान की आवश्यकता और परिपक्वता के आधार पर फूलगोभी के चार वर्ग बनाये गए हैं। इनमें अगेती समूह की फूलगोभी सितंबर-अक्टूबर में तैयार हो जाती है। फूलगोभी की किस्मों का चुनाव सोच-समझकर करना चाहिए क्योंकि अगेती किस्मों को मध्य या मध्य पछेता लगाने से बटनिंग (बहुत छोटे फूल बनना) की समस्या आती है और विपरीत स्थिति में पौधे की बढ़वार तो होती रहती है परन्तु फूल का बनना उचित समय आने पर ही होता है।

अगेती फूलगोभी कि उन्नत किस्में

पूसा मेघना: सितम्बर के अंतिम सप्ताह में कटाई के लिए तैयार, औसत पैदावार 100-120 क्विंटल/हेक्टेयर, फूल ठोस, 300-400 ग्राम के सफेद क्रीम रंग युक्त, पौधे छोटे आकार के तथा फसल अवधि 60-65 दिन होती है।

पूसा अश्विनी: अक्टूबर के मध्य में कटाई के लिए तैयार, औसत पैदावार 140-160 क्विंटल/हेक्टेयर, फूल ठोस,

500-600 ग्राम के सफेद हल्के क्रीम रंग युक्त, पौधे आकार में मध्यम तथा 65-70 दिन में फसल तैयार होती है।

पूसा कार्तिकी: अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में कटाई के लिए तैयार, औसत पैदावार 150-170 क्विंटल/हेक्टेयर, फूल ठोस, 550-700 ग्राम के और सफेद रंग युक्त, पौधे आकार में मध्यम से बड़े तथा 70-75 दिन में फसल तैयार होती हैं।

पूसा कार्तिक संकर: अगेती फूलगोभी की यह एक संकर प्रजाति है जो अक्टूबर के मध्य में तैयार हो जाती है। इसके फूल बहुत ठोस, 500-600 ग्राम के और सफेद हल्के क्रीम रंग के होते हैं, पौधे आकार में मध्यम, फसल अवधि 65-75 दिन और औसत पैदावार 140-160 क्विंटल/हेक्टेयर है। इन किस्मों के बीज की उपलब्धता के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली या राष्ट्रीय बीज निगम के केन्द्रों पर पता किया जा सकता है।

बीज और पौधशाला प्रबंधन

अगेती फूलगोभी की नर्सरी उगाना एक कठिन कार्य है इसीलिए नर्सरी की देखभाल विशेष रूप से करने की आवश्यकता होती है।

- अगेती फूलगोभी में बीज दर अधिक रखी जाती है क्योंकि अंकुरण कम होता है और प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या भी अधिक लगती है। सामान्यतः 500-750 ग्राम बीज से तैयार की गई पौध एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई हेतु पर्याप्त होती है।



- अगेती फूलगोभी की पौधशाला पर्याप्त नमी वाले स्थान पर बनानी चाहिए। उचित जल निकास की व्यवस्था करें। संभव हो तो मृदा जनित बीमारियों से प्रभावित भूमि में पौधशाला न बनायें।
- मई महीने में पौधशाला के लिए चयनित भूमि को प्लास्टिक शीट से ढककर सौलेराइजेशन से भूमि उपचार करें। बुवाई से एक सप्ताह पहले मिट्टी को केप्टान के 3 ग्रा./ली. पानी के घोल से तर भी करें।
- बुवाई के एक सप्ताह पहले 1 कि.ग्रा. ट्राइकोडर्मा वीरीडी को 100 कि.ग्रा. गोबर की खाद में मिला कर तैयार करें और इसे नर्सरी बैड में मिलायें। इससे आद्रगलन और मृदा जनित रोगों से बचाव होता है।
- पौध तैयारी के लिए बैड 3.0-5.0 मी. लंबाई में, 45 से.मी. चौड़ाई में तथा 20-30 सें.मी. उठी हुई बनायें। एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए लगभग 25 से 30 नर्सरी बैड पर्याप्त होती हैं।
- नर्सरी तैयारी के समय प्रत्येक बैड में 20-25 कि.ग्रा. अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद मिलायें।
- केप्टान या बाविस्टीन 2 ग्रा. प्रति कि.ग्रा. बीज की दर से या ट्राइकोडर्मा 5 ग्रा. प्रति कि.ग्रा. बीज के हिसाब से बीज उपचार करें।
- पौध को सख्त बनाने (हार्डनिंग) हेतु अंतिम 5-6 दिनों में सिंचाई एक दिन के अंतराल पर करें। विशेष रूप से अगेती फूलगोभी की पौध रोपाई सायंकाल में ही करें।
- रोपाई से पहले पौधों की जड़ों को ट्राइकोडर्मा 10 ग्रा. प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 30 मिनट तक डुबायें ताकि रोपाई के बाद सड़न रोग से बचाव किया जा सके।
- कम्पोस्ट 25 से 30 टन, नत्रजन 120 कि.ग्रा., फास्फोरस 100 कि.ग्रा. और पोटाश 60 कि.ग्रा. की दर से दें।
- गोबर की खाद या कम्पोस्ट की पूरी मात्रा खेत की तैयारी के समय रोपाई के तीन सप्ताह पूर्व प्रथम जुताई के दौरान भूमि में मिला दें।
- खेत की अंतिम जुताई के समय नत्रजन की आधी मात्रा तथा फास्फोरस व पोटाश की पूरी मात्रा भूमि में अच्छी तरह से मिला दें। शेष नत्रजन को बराबर दो हिस्सों में बांट कर एक हिस्सा रोपाई के एक महीने पश्चात निराई-गुड़ाई के साथ डालें तथा दूसरा हिस्सा फूल बनने की स्थिति में (लगभग 45-50 दिन बाद) मिट्टी चढ़ाते समय मिलाएं। पौधों की बढ़वार कम होने की स्थिति में 2-3 बार 10-15 ग्राम यूरिया प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें।
- गोभी के फूल में बोरॉन की कमी के कारण भूरापन तथा मोलिब्डेनम की कमी के कारण व्हीपटेल की समस्या आती है। इनसे बचाव के लिए 1.5 से 2.5 कि.ग्रा. बोरेक्स और 1.0 से 2.0 कि.ग्रा. सोडियम या अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से अन्य उर्वरकों के साथ भूमि में मिलायें।
- गोभी की अगेती फसल की रोपाई के समय वातावरणीय कारक अनुकूल तो नहीं होते लेकिन अधिक आयु की पौध (5-6 सप्ताह) और उठी हुई मेड़ियों (15-20 सें.मी.) पर रोपाई करने से अच्छी फसल ले सकते हैं।
- अगेती फूलगोभी के पौधे आकार में छोटे से मध्यम आकार के होते हैं इसलिए फसल अंतराल कम रखें और प्रति हेक्टेयर अधिक पौधे लगाकर पैदावार बढ़ायें।
- अगेती फूलगोभी के लिए फसल पंक्तियों के बीच 45 सें. मी. एवं पौध से पौध के बीच 30 सें.मी. (सितंबर परिपक्वता समूह) से 45 (अक्टूबर परिपक्वता समूह) सें.मी. रखें। रोपाई के तुरन्त बाद हल्की सिंचाई करें। अगेती फसल में रोपाई उपरांत कुछ पौधे मर जाते हैं या पौधे की कोपल क्षतिग्रस्त (ब्लाइडिंग) हो जाती है। इस स्थिति में पौधों की

उन्नत सस्य क्रियाएं

- फूलगोभी को अधिक खाद और उर्वरकों की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए प्रति हेक्टेयर सड़ी हुई गोबर की खाद या

उचित संख्या बनाये रखने के लिए 7-10 दिन में पुनः रोपण (गैप फिलिंग) करें। इसके लिए पौधशाला में कुछ पौधे बचा कर रखने चाहिए।

- बरसात के समय खरपतवार अधिक होते हैं इसलिए 15 दिन के अंतराल पर तीन गुड़ाई करें।
- खरपतवार नियंत्रण के लिए रोपाई से एक-दो दिन पहले स्टॉम्प 3.3 लीटर या बेसालीन 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर हल्की सिंचाई करें।
- रोपाई के 30 दिन बाद मिट्टी चढ़ाने से फसल की बढ़वार अच्छी होती है एवं पैदावार बढ़ती है।
- अगेती फसल में सिंचाई रोपाई के तुरन्त बाद तथा उसके पश्चात साप्ताहिक अंतराल पर आवश्यकता अनुसार करें।

प्रमुख रोग एवं कीट प्रबंधन

- कटुवा इल्ली गोभी के पौधों को रात्रिकाल में नुकसान पहुंचाती है। इसके नियंत्रण हेतु प्रकाश प्रपंच का प्रयोग वयस्क शलभों को पकड़ने के लिए करें तथा फोरेट 10जी 10 कि.ग्रा./हे. की दर से अंतिम जुताई के समय मिलाएं।
- हीरक पृष्ठ पतंगा गोभी में 50-60 प्रतिशत तक नुकसान पहुंचाता है जो पत्तियों की निचली सहत पर छोटे-छोटे छिद्र बना देता है। इसके नियंत्रण हेतु गोभी की प्रत्येक 25

कतारों के बाद दो कतार जाल फसल (ट्रेप क्रॉप) सरसों की लगायें। स्याइनोसिड (25 एस.सी.) 3.0 मि.ली. प्रति 10 लीटर पानी की दर से छिड़काव करें।

- तंबाकू की सुंडी छोटी अवस्था में पत्तों को खुरच कर खाती है तथा बड़ी अवस्था में गोल-गोल काटकर खाती है। इसके नियंत्रण हेतु अंडे के समूह को एकत्र कर नष्ट करें। एन.पी.वी. 250 एम.ई./हे. की दर से छिड़काव करें एवं मेलाथियान 2.0 मि.ली./ली. के हिसाब से पानी में मिलाकर छिड़काव करें।
- आर्द्रगलन रोग का प्रकोप नर्सरी अवस्था में अत्यधिक होता है। इसके नियंत्रण हेतु बीजों की बुवाई से पूर्व 3 ग्राम थीरम या केप्टान प्रति कि.ग्रा. बीज की दर से बीजोपचार करें।
- काला सड़न के कारण पत्तियों के बाहरी किनारों पर 'वी' आकार के हरिमाहीन एवं पानी में भीगे जैसे धब्बे दिखाई देते हैं। इसके नियंत्रण हेतु बीजों की बुवाई से पूर्व स्टेप्टोसाइक्लिन 250 मिग्रा. या बाँविस्टन 1 ग्रा./ली. पानी के घोल में 2 घंटे उपचारित कर छाया में सुखाकर बुवाई करें।

- श्रवण सिंह, बी.बी. शर्मा, आर.के. यादव,
वी.के. शर्मा और बी.एस. तोमर
शाक्रीय विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि
अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली

राष्ट्रीय नर्सरी पोर्टल का शुभारंभ



केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय नर्सरी पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री तोमर ने कहा कि बागवानी के माध्यम से देश के युवा बड़े उद्यमी बनकर जीडीपी में योगदान दे सकते हैं।

श्री तोमर ने कहा कि अर्थव्यवस्था को गति देने में बागवानी का क्षेत्र संभावित कृषि उद्यम के रूप में उभरा है। देश की पोषण सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन व रोजगार सृजन कार्यक्रमों में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती जा रही है। बागवानी का क्षेत्र न केवल फसल विविधीकरण के लिए किसानों को कई प्रकार के विकल्प प्रदान करता है, बल्कि बड़ी संख्या में कृषि उद्योगों को बनाए रखने के लिए प्रचुर अवसर भी प्रदान करता है, जो रोजगार के बड़े अवसर पैदा करते हैं।

श्री तोमर ने कहा कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने नर्सरियों के लिए 'ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफार्म' स्थापित किया है, ताकि किसान/उत्पादक और अन्य हितधारक अपने आसपास के क्षेत्रों में उपलब्ध क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल की उपलब्धता की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकें। इस पोर्टल के माध्यम से नर्सरियों के संचालक अपनी प्रोफाइल प्रदर्शित कर सकेंगे और बिक्री ऑफर डाल सकेंगे। प्लांटिंग मटेरियल के खरीदार भी सीधे ऑनलाइन पूछताछ कर सकेंगे और अपनी जरूरत से मिलते-जुलते बिक्री ऑफर देख पाएंगे। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा विकसित इस नए राष्ट्रीय नर्सरी पोर्टल से खरीददारों को नर्सरियों तक आसानी से पहुंचने में मदद मिलेगी और साथ ही वे क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल की उपलब्धता, कीमत आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। इसी तरह नर्सरियों को भी बाजार मांग का पता चलेगा। खरीददारों का नर्सरियों से सीधा संपर्क होने से नर्सरियों को उनके प्लांटिंग मटेरियल का बेहतर दाम मिल पाएगा व बेहतर उपज तथा क्वालिटी बनाए रखने के लिए समय से सलाह प्राप्त कर सकेंगे। यह पोर्टल नर्सरियों व खरीदारों के बीच दूरी खत्म करने में मदद करेगा व क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने में भी सहयोग करेगा।

नेशनल नर्सरी पोर्टल में आप नीचे दिये गये लिंक से प्रवेश कर सकते हैं-

<http://www.nhb.gov.in>



ड्रैगन फल की आधुनिक खेती

ड्रैगन फल (हीलोसेरस प्रजातियां) एक अधिपादप, मरुद्भिद्, बेल की तरह तेजी से बढ़ने वाला नागफनी है। यह वंश हीलोसेरियस के कुल कैक्टैसीई में उपकुल कैक्टोएसाइड से संबंधित है। इसे पीताया, चांदनी, नाइट फुलिंग सेरेस, स्ट्राबेरी पीयर, बेले ऑफ द नाइट और कंड्रेला प्लांट के नाम से भी जाना जाता है इसकी त्वचा पर ब्रक्ट्स स्केल्स का आवरण होता है। इसलिए इसे ड्रैगन फल कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति मुख्य रूप से मध्य और दक्षिणी अमेरिका में मानी जाती है। इसकी खेती मलेशिया, इंडोनेशिया, ताइवान, थाईलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश और वियतनाम सहित कई दक्षिणी पूर्वी देशों में की जाती है। अब ड्रैगन फल की खेती भारत में भी की जाने लगी है। यह बहुत ही पौष्टिक और स्वादिष्ट फल है। इसे 'सुपर फूड्स' भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें विटामिन, खनिज, फाइबर, प्रोटीन और ऑक्सीकरणरोधी तत्व भरपूर मात्रा में पाये जाते हैं। ड्रैगन फल की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं-

- हीलोसेरस अन्डेट्स : फल गुलाबी-लाल, कई छोटे काले बीज के साथ सफेद गुदा।
- हीलोसेरस कोटारिकेंसिस : फल लाल, कई छोटे काले बीज के साथ लाल बैंगनी गुदा।
- हीलोसेरस पॉल्लिरिजस : फल लाल, कई छोटे काले बीज के साथ लाल गुदा।
- हीलोसेरस परपुसी : फल लाल, कई छोटे काले बीज के साथ लाल गुदा।

जलवायु एवं मृदा

ड्रैगन फल विभिन्न तापमान परिस्थितियों में उगाया जा सकता है, लेकिन उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्र इसकी खेती के लिए सबसे उपयुक्त हैं। इसकी खेती कम वर्षा (50 सेंटीमीटर) तथा तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस वाले क्षेत्रों में आसानी से की जाती है। यह काफी गर्म तापमान सहन कर सकता है। इसकी कुछ प्रजातियां 38 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान सहन कर सकती हैं। परन्तु तापमान 12 डिग्री सेल्सियस से कम होने पर तना परिगलन (स्टेम नेक्रोसिस) हो जाता है। हीलोसेरस प्रजातियां अधिपादप होती हैं, इसलिये ये आम तौर पर अर्धछाया स्थिति में उगाई जाती हैं। यह विभिन्न प्रकार की मृदा में उगाया जा सकता है, जबकि अच्छी कार्बनिक पदार्थ तथा आंतरिक जल निकास वाली रेतीली मृदा इसकी खेती की लिए उपयुक्त है।

भूमि की तैयारी

मिट्टी की भुरभुरी होने तक जुताई करनी चाहिए और अच्छी तरह से विघटित कार्बनिक खाद उचित मात्रा में मिलानी चाहिए।

पौध प्रवर्धन

ड्रैगन फल का प्रवर्धन कलम द्वारा आसानी से किया जाता है। इसके अलावा इसे बीज तथा कृत्रिम परिवशीय

(इन विट्रो) विधि द्वारा भी प्रवर्धित किया जा सकता है। कलम विधि द्वारा प्रवर्धित किये गए पौधे बहुत जल्दी, एक वर्ष से भी कम समय में फल देने योग्य हो जाते हैं। जबकि बीज द्वारा प्रवर्धित किये गए पौधे तीन वर्ष में फल देने योग्य होते हैं। कमल द्वारा प्रसारण अच्छा माना जाता है क्योंकि कलम द्वारा प्रवर्धित पौधे पूर्वज पौधे के समान गुण वाले होते हैं। कलम की लंबाई 20 सेंटीमीटर रोपण के लिए ली जाती है। इन कलमों को गमलों में रोपित किया जाता है, गमलों को अच्छी तरह से विघटित फार्म यार्ड मेन्युर : ऊपरी मृदा : रेतीली मृदा के 1:1:2 के रोपण मिश्रण में रोपित किया जाता है। इन गमलों से पौधों को मुख्य बाग में रोपण से पहले छाया में रखना चाहिए। बाग में रोपण के समय पौधे से पौधे के बीच की दूरी 2 मीटर गुणा 2 मीटर जाती है और गड्ढे का आकार 60 सेंटीमीटर गुणा 60 सेंटीमीटर गुणा 60 सेंटीमीटर उपयुक्त होता है। इन गड्ढों को उपरी मृदा, कम्पोस्ट तथा 100 ग्राम सुपरफॉस्फेट से भरा जाना चाहिए।



ड्रैगन फल को 'सुपर फूड्स' भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें विटामिन, खनिज, फाइबर, प्रोटीन और ऑक्सीकरणरोधी तत्व भरपूर मात्रा में पाये जाते हैं।

पौध घनत्व

पौधों के बीच की दूरी उनको दिए जाने वाले लकड़ी या अन्य ठोस स्तंभ के सहारे पर निर्भर करती है। उर्ध्वाधर समर्थन में, पंक्तियों के बीच की दूरी 2 से 3 मीटर रखी जाती है। अतः 2000 से 3750 कलमों प्रति हेक्टेयर तथा 3 कलमों प्रति समर्थन लगायी जाती हैं। जबकि क्षैतिज समर्थन में, कलमों को 50-75 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाया जाता है। इसलिए इसमें पौध घनत्व उर्ध्वाधर समर्थन की अपेक्षा कहीं ज्यादा होता है। इसमें पौध घनत्व 6500 कलम प्रति हेक्टेयर होता है। अन्य बागवानी कार्य आसानी से करने के लिए इन स्तंभों की ऊंचाई 1.5 मीटर उर्ध्वाधर समर्थन में तथा 1.10 मीटर क्षैतिज समर्थन में रखी जानी चाहिए।

प्रारंभिक कटाई-छंटाई

ड्रैगन फल एक अधिपादप होता है, जो रंगते-चढ़ते किसी भी प्राकृतिक और कृत्रिम समर्थन से स्वाभाविक रूप से चिपक जाता है। इसकी उचित वृद्धि व विकास के लिए इन्हें लकड़ी या अन्य ठोस स्तंभ पर प्रशिक्षित किया जाता है। बिना किसी सहारे के इसकी खेती करने में परागण व फलों की तुड़ाई में कठिनाई आती है। प्रारंभिक कटाई छंटाई/प्रशिक्षण के समय छोटे व अपरिपक्व पौधों को इन स्तंभों से बांधा जाता है।

खाद व उर्वरक

इसकी सतही जड़ प्रणाली है जो कि पोषक तत्वों की कम से कम मात्रा को भी आसानी से ग्रहण कर लेती है। खनिज

और कार्बनिक पदार्थ इसकी वृद्धि के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। ड्रैगन पौधे को 10-15 किलोग्राम कार्बनिक खाद प्रति पौधा प्रति वर्ष देना चाहिए तथा प्रति वर्ष 2 किलोग्राम मात्रा और बढ़ाई जानी चाहिए। अकार्बनिक उर्वरक इसके बेहतर विकास के लिए दिए जाते हैं। फल बनने के समय पोटाश की उच्च मात्रा और नाइट्रोजन की कम मात्रा बेहतर फल की गुणवत्ता के लिए दी जाती है।

सिंचाई

यह बहुत कम वर्षाकाल तथा कई महीनों तक सूखा सहन कर सकता है। परन्तु एक अच्छी गुणवत्ता वाले फल उत्पादन के लिए नियमित सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। नियमित सिंचाई पौधे को पर्याप्त जल संचय करने में सक्षम बनाती है। जो कि न केवल फूल निकलने के समय, बल्कि फल के विकास को भी सुनिश्चित करती है।

परागण

आनुवंशिक विविधता की कमी और परागण कीटों की अनुपस्थिति के कारण फल विकास सुनिश्चित करने लिए ड्रैगन फल में हाथ द्वारा परागण किया जाता है। इसमें हाथ द्वारा परागण सरल होता है, क्योंकि इसके पुष्प अंगों का आकार विशाल होता है। परागण फूलों के खुलने से पहले सायं 4.30 बजे से दूसरे दिन सुबह 11.00 बजे तक किया जाना चाहिए।

कीट एवं बीमारी

अभी तक ड्रैगन फल की खेती में किसी तरह की बीमारी एवं कीट नहीं पाये गये हैं।

फलों की तुड़ाई

ड्रैगन फल का परिपक्वता चरण के समय त्वचा का रंग बहुत देर से बदलता है। यह फूल आने के 22 से 27 दिन बाद हरे से लाल या गुलाबी रंग में परिवर्तित हो जाता है। यह समय विभिन्न प्रजातियों में अलग-अलग होता है। इसकी पहली फल कटाई कलम रोपण के 18 महीने बाद शुरू होती है। पारिस्थितिकी के आधार पर इसमें फूल से फल बनने के बीच की अवधि 27 से 33 दिन की होती है। इसकी उपज पौध घनत्व पर निर्भर करती है। यह 10 से 30 टन प्रति हेक्टेयर होती है। इसमें डंटल नहीं होने के कारण इसकी तुड़ाई मुश्किल होती है। फलों को तोड़ने में अक्सर त्वचा को नुकसान पहुंचता है।

- कुलदीप सिंह, सुनील कुमार एवं ओमप्रकाश अवस्थी
फल एवं औद्योगिकी प्रौद्योगिकी संभाग
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली



जैविक खाद बनाने की विधि, उपयोग एवं लाभ

हरित क्रांति के फलस्वरूप अन्न उत्पादन में देश आत्मनिर्भर हुआ परन्तु इसके दुष्परिणाम भी सामने आये, जैसे मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा में कमी, मृदा क्षारियता, मृदा उर्वरता में गिरावट, रसायनों के अवशेष के फलस्वरूप मृदा, जल एवं वायु प्रदूषण तथा मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव। इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय जैविक खेती ही है।

भारतीय कृषि में जैविक खाद का महत्वपूर्ण स्थान है एवं इनका अधिक से अधिक मात्रा में प्रयोग कर उर्वरकों की खपत कम की जा सकती है। जैविक खाद मृदा में मौजूद लाभकारी सूक्ष्म जीवों का वैज्ञानिक तरीकों से चुनाव कर प्रयोगशालाओं में तैयार की जाती है। वायुमंडल के नत्रजन व भूमि के फास्फोरस को पौधों को उपलब्ध कराने वाले जीवाणुओं को जीवित अवस्था में लिग्नाइट व पिसे हुए कोयले में मिलाकर जैविक खाद तैयार की जाती है। जैविक खाद में इन लाभदायक जीवाणुओं की संख्या एक ग्राम में दस करोड़ से अधिक रखी जाती है। ये जीवाणु निम्न प्रकार के होते हैं:

राइजोबियम - यह एक मृदा बैक्टेरिया है जो दलहनी फसलों की जड़ों पर गुलाबी रंग की गांठें बनाकर उनमें रहते हैं तथा हवा में से नत्रजन लेकर पौधों को उपलब्ध कराते हैं।

एजेटोबेक्टर - यह जीवाणु खाद बिना दलहन वाली फसलों में उपयोग की जाती है। यह जमीन में स्वतंत्र रूप से रहकर हवा की नत्रजन को ग्रहण कर भूमि में छोड़ते हैं, जो पौधों को उपलब्ध होती हैं।

फास्फेट विलेयक जीवाणु (पी.एस.बी.) - जीवाणु खाद पी. एस.बी. इसी अघुलनशील फास्फोरस को पौधों को घुलनशील बनाकर उपलब्ध कराता है।

एजोस्पाइरिलम कल्चर - यह जीवाणु खाद खरीफ के मौसम में धान, मोटे अनाज तथा गन्ने की फसल के लिए विशेष उपयोगी है। इनके अलावा गेहूं व जौ की फसल के लिए भी लाभकारी है। इसके प्रयोग से फसल के उत्पादन में 10-12 प्रतिशत वृद्धि होती है तथा 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नत्रजन की बचत होती है।

नील हरित शैवाल - ये शैवाल मिट्टी के सदृश्य सूखी पपड़ी के टुकड़ों के रूप में होते हैं तथा धान की फसल के लिए जिसमें पानी भरा रहता है विशिष्ट लाभकारी होते हैं। ये सूक्ष्म जीवाणु 20-30 किलोग्राम नत्रजन प्रति हेक्टेयर उपलब्ध कराते हैं तथा फसल की 10-15 प्रतिशत उपज में बढ़ोतरी करते हैं। 10 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर पानी भरे खेत में छिड़काव के लिए पर्याप्त होती है।

जैविक खाद के लाभ

- ये जीवाणु फसलों की पोषक तत्वों की जरूरत को पूरा कर उनकी उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाते हैं।
- ये सूक्ष्म जीवाणु मृदा में मौजूद फास्फोरस को घुलनशील बनाकर पौधों के लिए उपलब्धता बढ़ाते हैं।
- ये सूक्ष्म जीव कुछ मात्रा में सूक्ष्म आवश्यक पोषक तत्वों

वर्मी कम्पोस्ट खाद

वर्मी कम्पोस्ट केंचुआ की मदद से निर्मित जैविक खाद है, जिसे किसान भाई स्वयं बना सकते हैं।

वर्मी कम्पोस्ट बनाने की विधि

सर्वप्रथम उपयुक्त स्थान जिसमें उपयुक्त नमी एवं तापमान निर्धारित किये जा सके, का चयन कर इसके ऊपर एक छप्पर या अस्थायी शेड बनाया जाता है। शेड की लंबाई-चौड़ाई वर्मी टैंक की संख्या पर निर्भर करती है। वर्मी टैंक का मानक आकार 1 मी. चौड़ा, 0.5 मी. गहरा तथा 10 मी. लम्बा होता है। उपयोग सामग्री के रूप में कृषि अवशेष, जलकुंभी, केले एवं बबूल की पत्तियां, अन्य हरी एवं सूखी पत्तियां, पेड़ों की हरी शाखायें, घास, सड़ी-गली सब्जियां एवं फल, घरेलू कचरा एवं पशुओं का गोबर आदि को उपयोग में लाया जाता है।

नमीयुक्त वानस्पतिक कचरे में गोबर का घोल मिलाकर 15 दिनों तक सड़ाया जाता है और वर्मी टैंक में इसकी 6 इंच की तह लगा देते हैं। इस 6 इंच की परत पर लगभग 6 इंच तक पका हुआ गोबर डाला जाता है। इस गोबर की तह पर 500-1000 केंचुए प्रति वर्गमीटर के हिसाब से डाले जाते हैं। वर्मी कम्पोस्टिंग के लिए केंचुआ की सर्वाधिक उपयुक्त प्रजातियां आइसिनिया फोयटिडा, यूड्रिलस यूजिनी एवं परियोनिक्स एक्सावेटस हैं।

इस परत पर 1 फीट ऊंची अधसड़ें एवं बारीक वानस्पतिक कचरे की तह लगा दी जाती है। इस प्रकार ढेर की ऊंचाई 2-3 फीट तक हो जाती है। अब इस डोम के आकार के ढेर को जूट के बोरों से ढक दिया जाता है। शेड में सदा अंधेरा बना रहना चाहिए, क्योंकि अंधेरे में केंचुए ज्यादा सक्रिय रहते हैं। इसलिये शेड के चारों ओर घास-फूस या बोरे लगा देने चाहिए। बोरों के ऊपर नियमित रूप से आवश्यकता अनुसार पानी का छिड़काव किया जाता है, ताकि टैंक में नमी बनी रहे। टैंक के ढेर को लगभग 25-30 दिन के बाद हाथों या लोहे के पंजे की सहायता से धीरे-धीरे पलटते हैं जिससे वायु का संचार तथा ढेर का तापमान भी ठीक रहता है। यह क्रिया 2-3 बार दोहरायी जाती है। टैंक के अन्दर का तापमान 25-30 डिग्री सेंटीग्रेड एवं नमी 30-35 प्रतिशत रहनी चाहिए।

पानी के उचित प्रयोग से तापमान एवं नमी को नियंत्रित किया जा सकता है। मानक आकार के टैंक के लिए प्रतिदिन

जैसे- जिंक, तांबा, सल्फर, लोहा, बोरोन, कोबाल्ट व मोलिब्डिनम इत्यादि पौधों को प्रदान करते हैं।

- ये सूक्ष्म जीवाणु खेती में बचे हुए कार्बनिक अपशिष्टों को सड़ाकर मृदा में कार्बनिक पदार्थ की उचित मात्रा बनाये रखते हैं।
- ये सूक्ष्म जीवाणु पादप वृद्धि करने वाले हार्मोन्स, प्रोटीन, विटामिन एवं अमीनो अम्ल का उत्पादन करते हैं तथा ये सूक्ष्म जीवाणु मृदा में पनप रही रोग जनक फफूंद नष्ट कर लाभकारी जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि करते हैं।
- इन जीवाणुओं के प्रयोग से लगभग 15-30 प्रतिशत फसलोत्पादन बढ़ता है और उत्पाद की गुणवत्ता बहुत अच्छी रहती है।
- इन सूक्ष्म जीवाणुओं के प्रयोग से मृदा की जलधारण शक्ति व उर्वरा शक्ति बढ़ती है जिससे फसलोत्पादन बढ़ता है।
- ये जैविक खाद प्रत्येक मौसम में प्रति फसल लगभग 20 से 30 किलोग्राम नत्रजन प्रति हैक्टेयर तथा फास्फोरस को घुलनशील बनाने वाले जीवाणु प्रति हैक्टेयर लगभग 30 से 40 किलोग्राम फास्फोरस प्रति फसल उपलब्ध कराते हैं।

जैविक खाद उपयोग की विधि

जीवाणु खाद का फसल उत्पादन में प्रयोग कई प्रकार से किया जा सकता है, जैसे-

क) बीजोपचार द्वारा- आवश्यकतानुसार पानी में 150 ग्राम गुड 1 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर गर्म करें। इसे ठंडा कर इसमें जीवाणु खाद के तीन पैकेट (एक हैक्टेयर क्षेत्र हेतु) घोलें। अब इस घोल को एक हैक्टेयर क्षेत्र के लिए आवश्यक बीज की मात्रा पर छिड़कते हुए हल्के हाथ से बीजों को पलटते जायें, जिससे बीजों के ऊपर जीवाणु खाद की एक बारीक परत चढ़ जाए। अब बीजों को किसी छायादार स्थान पर सुखाकर शीघ्र ही बुआई करें।

ख) जड़ों के उपचार द्वारा- फल, सब्जियों एवं अन्य पौधों की जड़ों को रोपाई से पूर्व जीवाणु खाद के घोल में लगभग 15 मिनट तक डुबोकर रखें तथा बाद में इनकी भूमि में रोपाई करनी चाहिए।

ग) भूमि उपचार द्वारा- जीवाणु खाद को नम मिट्टी में अच्छी प्रकार से मिलाकर पूरे खेत में सायंकाल छिटक कर सिंचाई कर देनी चाहिए।





लगभग 30-90 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। लगभग 60-75 दिनों में वर्मी कम्पोस्ट तैयार हो जाती है। इस समय ढेर में चाय की पत्ती के समान केंचुए के द्वारा निकाली गई कास्टिंग दिखाई देगी। इस खाद को शेड से निकाल कर पालीथीन की चादर पर रखा जाता है। 2-3 घंटे के पश्चात केंचुए पॉलीथीन की सतह पर आ जाते हैं। वर्मी कम्पोस्ट को अलग कर नीचे एकत्र हुए केंचुओं को एकत्रित कर पुनः वर्मी कम्पोस्ट बनाने के लिए प्रयोग करें। इस खाद को छाया में सुखाकर नमी कम कर लेते हैं तथा उसे बोरी में भरकर 8-12 प्रतिशत नमी में एक साल तक भंडारण कर सकते हैं।

एक किलोग्राम वजन में लगभग 1000 वयस्क केंचुए होते हैं। एक दिन में 1 किलोग्राम वयस्क केंचुए लगभग 5 किलोग्राम कचरे को खाद में बदल देते हैं। ऊपर बताई गई विधि से मात्र 60-75 दिन में 10 गुणा 1 गुणा 0.5 मीटर टैंक से लगभग 5-6 कुंटल वर्मी कम्पोस्ट तैयार हो जाती है जिसके लिए लगभग 10-12 कुंटल कच्चा पदार्थ लगता है।

वर्मी कम्पोस्ट प्रयोग करने के लाभ

- वर्मी कम्पोस्ट मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की वृद्धि करता है तथा भूमि में जैविक क्रियाओं को निरन्तरता प्रदान करता है।
- वर्मी कम्पोस्ट का भूमि में प्रयोग करने से भूमि भुरभुरी एवं लंबे समय तक उपजाऊ बनती है। भूमि में केंचुओं की सक्रियता से पौधों की जड़ों के लिए उचित वातावरण बनता है जिससे उनका अच्छा विकास होता है।
- वर्मी कम्पोस्ट खेत में दीमक एवं अन्य नुकसान करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देती है। इससे कीटनाशक की लागत में कमी आती है।
- इसके प्रयोग से भूमि में लाभप्रद सूक्ष्म जीवाणुओं जैसे नत्रजन और फास्फोरस स्थिरीकरण, जीवाणु, प्रोटोजोआ, फफूंदी आदि की संख्या में वृद्धि होती है, जो मिट्टी में पौधों के लिए भोज्य पदार्थ को सरल रूप में उपलब्ध कराते हैं।
- वर्मी कम्पोस्ट में नत्रजन की मात्रा 1 से 5 प्रतिशत, फास्फोरस 1 से 1.5 प्रतिशत तथा पोटाश 1.5 से 2.0 प्रतिशत तक पोषक तत्व पाये जाते हैं।
- केंचुए के विष्ठा में पेरीट्रापिक झिल्ली होती है, जो भूमि में धूलकणों से चिपक कर भूमि से वाष्पीकरण रोकती है।

वर्मी कम्पोस्ट बनाते समय सावधानियां

- कभी भी आक तथा धतूरे के पत्ते इस मिश्रण में ना डालें अन्यथा इसके जहरीले प्रभाव से केंचुए मर सकते हैं।
- वर्मी कम्पोस्ट का शेड छायादार जगह पर ही बनाया जाना चाहिए तथा बेड पर अंधेरा बनाए रखना चाहिए क्योंकि केंचुए अंधेरे में ज्यादा क्रियाशील होते हैं।
- सड़े-गले कार्बनिक पदार्थ व गोबर को अच्छी प्रकार मिलाना चाहिए ताकि कार्बन-नाइट्रोजन का अनुपात संतुलित रहे।
- कभी भी ताजा गोबर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे निकलने वाली गर्मी (गैस) से केंचुए मर सकते हैं एवं दीमक का आक्रमण हो सकता है। इस प्रकार गोबर 10-15 दिन पुराना होना चाहिए।
- वर्मी कम्पोस्ट बेड का तापमान 25-30 डिग्री सेल्सियस तथा नमी 30-35 प्रतिशत तक बनाए रखनी चाहिए।
- कठोर टहनियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। खरपतवार अवशेषों को भी फूल आने के पूर्व ही काम में लेना चाहिए।
- खरपतवार तथा कूड़े-कचरे में प्लास्टिक, कांच तथा पत्थर आदि नहीं होने चाहिए।
- वर्मी कम्पोस्ट बेड को तैयार कर लेने के 5-6 दिन बाद ही केंचुए छोड़े जाने चाहिए क्योंकि यदि छिड़काव के दौरान गड्ढे में पानी अधिक हो गया तो गड्ढा पक्का होने के कारण रिसेगा नहीं जिससे केंचुए मर सकते हैं।
- गड्ढों को चीटियों, कीड़ों-मकोड़ों, मुर्गियों, कौओं तथा पक्षियों आदि से सुरक्षित रखें।

जैविक खेती में जैविक खादों का योगदान

- जैविक खादों के प्रयोग से मृदा का जैविक स्तर बढ़ता है, जिससे लाभकारी जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाती है और मृदा काफी उपजाऊ बनी रहती है।
- जैविक खाद पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक खनिज पदार्थ प्रदान कराते हैं, जो मृदा में मौजूद सूक्ष्म जीवों के द्वारा पौधों को मिलते हैं जिससे पौधों स्वस्थ बनते हैं और उत्पादन बढ़ता है।
- रासायनिक खादों के मुकाबले जैविक खाद सस्ते, टिकाऊ तथा बनाने में आसान होते हैं।
- इनके प्रयोग से मृदा में ह्यूमस की बढ़ोतरी होती है व मृदा की भौतिक दशा में सुधार होता है।



- पौध वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्वों जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश तथा काफी मात्रा में गौण पोषक तत्वों की पूर्ति जैविक खादों के प्रयोग से ही हो जाती है।
- कीटों, बीमारियों तथा खरपतवारों का नियंत्रण काफी हद तक फसल चक्र, कीटों के प्राकृतिक शत्रुओं, प्रतिरोध किस्मों और जैव उत्पादों द्वारा ही कर लिया जाता है।
- जैविक खादें सड़ने पर कार्बनिक अम्ल देती हैं जो भूमि के अधुलनशील तत्वों को घुलनशील अवस्था में परिवर्तित कर देती हैं, जिससे मृदा का पीएच मान 7 से कम हो जाता है। अतः इससे सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ जाती है।

यह तत्व फसल उत्पादन में आवश्यक है।

- जैविक खादों के प्रयोग से पोषक तत्व पौधों को काफी समय तक मिलते हैं। यह खादें अपना अवशिष्ट गुण मृदा में छोड़ती हैं। अतः एक फसल में इन खादों के प्रयोग से दूसरी फसल को लाभ मिलता है। इससे मृदा उर्वरता का संतुलन ठीक रहता है।

- विनोद कुमार शर्मा, कपिल आत्माराम चोभे, मंदिरा बर्मन, सर्वेन्द्र कुमार, चिरंजीव कुमावत एवं अभिक पात्रा
मृदा विज्ञान, एवं कृषि रसायन विज्ञान संभाग
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली

तलचर फर्टिलाइजर को विशेष सब्सिडी



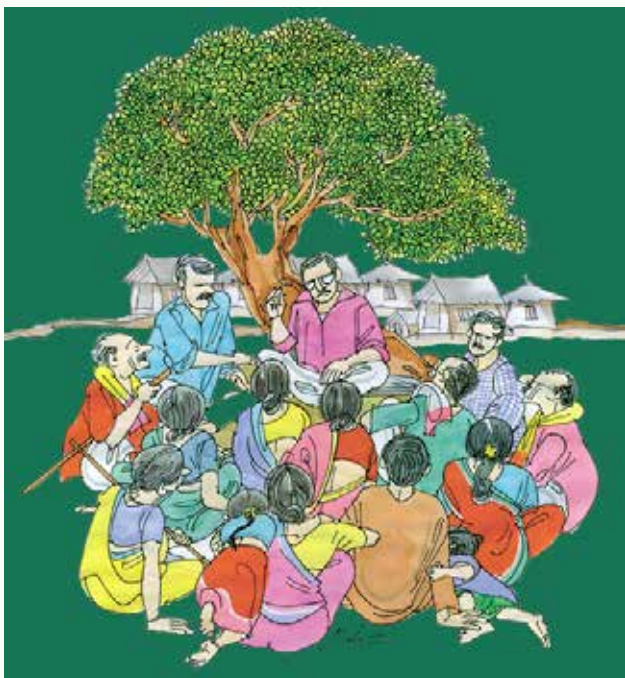
- तलचर फर्टिलाइजर्स कोयले की गैसीकरण प्रक्रिया से यूरिया का उत्पादन करेगी।
- यूरिया का आयात 12.70 लाख टन तक घटाने में मिलेगी मदद।
- देश में कोयले की अकूत भंडार है, इसलिए यूरिया के दामों में अस्थिरता नहीं आएगी।

केन्द्रीय कैबिनेट ने तलचर फर्टिलाइजर लिमिटेड (टीएफएल)के लिए विशेष सब्सिडी को मंजूरी दी है। इसके तहत टीएफएल कोल गैसिफिकेशन यानी कोयले की गैसीकरण प्रक्रिया से यूरिया का उत्पादन करेगी। इससे देश को यूरिया आयात में 12.70 लाख टन तक कटौती करने में मदद मिलेगी।

टीएफएल का गठन वर्ष 2015 में हुआ था। यह गेल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल), राष्ट्रीय कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफएल) तथा फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एफसीआईएल) का संयुक्त उपक्रम है। टीएफएल इस वक्त एफसीआईएल के एक पूर्ववर्ती संयंत्र का पुनरुद्धार कर रही है। इसके तहत यह उड़ीसा के तलचर में एक ग्रीनफील्ड यूरिया संयंत्र स्थापित कर रही है।

इसकी क्षमता 12.70 लाख टन सालाना होगी। इसकी स्थापना पर 13,277.21 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहन देने के लिए देश में पहली बार इस तकनीक आधारित विशिष्ट सब्सिडी को अनुमोदन दिया है। गोयल ने कहा कि कोयला गैसीकरण आधारित संयंत्र रणनीतिक लिहाज से महत्वपूर्ण है। वजह यह है देश में कोयले कोई कमी नहीं है और इसके दाम में भी अस्थिरता नहीं आती है। इससे प्राकृतिक गैस का आयात घटाने में और किसानों के लिए पर्याप्त यूरिया मुहैया कराने में भी बेहद मदद मिलेगी। (पेट्र)



कितनी शसक्त हैं हमारी पंचायतें

केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने वर्ष 2015-2016 में विकेंद्रीकृत रिपोर्ट जारी की थी जिसके अनुसार, देश में कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जिसने पंचायतों को उनके अधिकार दिये हों। कुछ राज्यों जैसे केरल, कर्नाटक में 11वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल 29 विषयों में लगभग 22-27 विषयों का हस्तांतरण पंचायतों को किया गया है, लेकिन कुछ राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश में केवल 4-7 विषयों का हस्तांतरण किया गया है।

- 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ। अतः 24 अप्रैल 'राष्ट्रीय पंचायत दिवस' के रूप में मनाया जाता है।
- इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में भाग-9 जोड़ा गया था।
- 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसके तहत पंचायतों के अंतर्गत 29 विषयों की सूची की व्यवस्था की गई।

11वीं अनुसूची में शामिल विषय

1. कृषि (कृषि विस्तार शामिल)। 2. भूमि विकास, भूमि सुधार कार्यान्वयन, चकबंदी और भूमि संरक्षण। 3. लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और जल-विभाजक क्षेत्र का विकास। 4. पशुपालन, डेयरी उद्योग और कुक्कुट पालन। 5. मत्स्य उद्योग। 6. सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी। 7. लघु वन उपज। 8. लघु उद्योग जिसके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी शामिल हैं। 9. खादी, ग्राम उद्योग एवं कुटीर उद्योग। 10. ग्रामीण आवासन। 11. पेयजल। 12. ईंधन और चारा। 13. सड़कें, पुलिया, पुल, फेरी, जलमार्ग और अन्य संचार साधन। 14. ग्रामीण विद्युतीकरण, जिसके अंतर्गत विद्युत का वितरण शामिल है। 15. अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत। 16. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। 17. शिक्षा, जिसके अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय भी हैं। 18. तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा। 19. प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा। 20. पुस्तकालय। 21. सांस्कृतिक क्रियाकलाप। 22. बाजार और मेले। 23. स्वास्थ्य और स्वच्छता (अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और औषधालय)। 24. परिवार कल्याण। 25. महिला और बाल विकास। 26. समाज कल्याण (दिव्यांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याण)। 27. दुर्बल वर्गों का तथा विशिष्टतया अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का कल्याण। 28. सार्वजनिक वितरण प्रणाली। 29. सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण।

स्वतंत्रता के पश्चात पंचायती राज की स्थापना लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा को साकार करने के लिये उठाए गये महत्वपूर्ण कदमों में से एक थी। वर्ष 1993 में संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता मिली थी। इसका उद्देश्य था देश की करीब ढाई लाख पंचायतों को अधिक अधिकार प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाना। उम्मीद थी कि ग्राम पंचायतें अपने स्थानीय जरूरतों के अनुसार योजनाएं बनाएंगी और उन्हें लागू करेंगी।

आजादी के बाद वर्ष 1957 में योजना आयोग (जिसका स्थान अब 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग ने ले लिया है) द्वारा 'सामुदायिक विकास कार्यक्रम' और 'राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम' के अध्ययन के लिये 'बलवंत राय मेहता समिति' का गठन किया गया। नवंबर 1957 में समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी जिसमें त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था - ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर एवं जिला स्तर लागू करने का सुझाव दिया गया।

वर्ष 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों स्वीकार कीं तथा गांधी जी के जन्मदिन 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले (राजस्थान) में तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू द्वारा देश की पहली त्रि-स्तरीय पंचायत व्यवस्था का उद्घाटन किया गया।

वर्ष 1993 में 73वें व 74वें संविधान संशोधन से भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ।

73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992

- 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 तत्कालीन प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव के कार्यकाल में प्रभावी हुआ।
- विधेयक के संसद द्वारा पारित होने के बाद 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और 24 अप्रैल 1993



केंद्र ने पंचायतों को 8923.8 करोड़ रुपये जारी किए

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) को अनुदान उपलब्ध कराने के लिए 25 राज्यों में पंचायतों को 8923.8 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। ये अनुदान पंचायती राज संस्थानों की सभी तीन श्रेणियों- गांव, प्रखंड और जिला के लिए हैं। यह वर्ष 2021-22 के लिए 'मुक्त अनुदान' की पहली किस्त है। इसका उपयोग आरएलबी द्वारा अन्य चीजों के अतिरिक्त कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए आवश्यक विभिन्न रोकथाम संबंधी तथा राहत उपायों के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार यह इस महामारी से लड़ने के लिए पंचायतों की तीनों श्रेणियों के संसाधनों को बढ़ाएगा।

15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, मुक्त अनुदान की पहली किस्त राज्यों को जून 2021 में जारी की जानी थी। वर्तमान में जारी कोविड-19 महामारी की स्थिति तथा पंचायती राज्य मंत्रालय की अनुशंसाओं को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने सामान्य कार्यक्रम से पहले ही अनुदान जारी करने का फैसला किया है।

राज्यों को केंद्र सरकार से प्राप्ति के 10 कार्य दिवसों के भीतर अनुदानों को आरएलबी को हस्तांतरित करना आवश्यक है। 10 कार्य दिवसों से परे किसी भी देरी के लिए राज्य सरकारों को ब्याज के साथ अनुदान जारी करना होगा।

वर्ष 2021-22 के लिए जारी की गई ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए मुक्त अनुदान की पहली किस्त का राज्य वार विवरण इस प्रकार है-

क्रम सं.	राज्य का नाम	करोड़ रुपये
1	आंध्र प्रदेश	387.8
2	अरुणाचल प्रदेश	34

3	असम	237.2
4	बिहार	741.8
5	छत्तीसगढ़	215
6	गुजरात	472.4
7	हरियाणा	187
8	हिमाचल प्रदेश	63.4
9	झारखंड	249.8
10	कर्नाटक	475.4
11	केरल	240.6
12	मध्य प्रदेश	588.8
13	महाराष्ट्र	861.4
14	मणिपुर	26.2
15	मिजोरम	13.8
16	ओडिशा	333.8
17	पंजाब	205.2
18	राजस्थान	570.8
19	सिक्किम	6.2
20	तमिलनाडु	533.2
21	तेलंगाना	273
22	त्रिपुरा	28.2
23	उत्तर प्रदेश	1441.6
24	उत्तराखंड	85
25	पश्चिम बंगाल	652.2
	कुल	8923.8



मंडियों ने दगा दिया

■ जनकवि बल्ली सिंह चीमा

कभी धान को कभी गेहूं को, तेरी मंडियों ने दगा दिया।
मेरी खेतियों से तुझे बैर है, तेरी नीतियों ने बता दिया।
मैं किसान हूँ मेरा हाल क्या, मैं तो आसमां की दया पे हूँ।
कभी मौसमों ने हंसा दिया, कभी मौसमों ने रुला दिया।
ये कहानियां, ये लफ्फाजियां, तेरे मुंह से मुझको जंची नहीं।
मेरे गांव में ये रिवाज है, कहा जो भी करके दिखा दिया।
मेरी जिंदगी तुझे क्या कहूँ, तू ही धूप है तू ही छांव है।
किसी शाम तूने रुला दिया, किसी शाम तूने हंसा दिया।
मैं गिरा तो गिर के उठा भी हूँ, यही फ़ख़ है कि झुका नहीं।
वो मशाल भी क्या मशाल है, जिसे आंधियों ने बुझा दिया।



छज्जे पर बैठी गौरैया
गुमसुम सोच रही
कहां गई आंगन की बैठक
आसन दादी का
बच्चों का कल्लोल
कीमती
सोना चांदी सा
घर क्या बंटा सबके सुइयां कोंच रही
कहां रोज चुग्गा
व्यंजन होली दीवाली में
अब जूठन तक नहीं छोड़ता
कोई थाली में
विस्मित गौरैया अपनी ही किस्मत कोस रही।

—नीलम श्रीवास्तव

घाघ की कहावतें

गहिर न जोतै बोंवै धान। सो घर कोठिला भरै किसान।।
गहरा न जोतकर धान बोने से उसकी पैदावार खूब होती है।

रोहिनी बरसै मृग तपै, कुछ कुछ अद्रा जाय।
कहै घाघ सुने घाघिनी, स्वान भात नहीं खाया।।
यदि रोहिणी बरसे, मृगशिरा तपै और आर्द्रा में साधारण वर्षा हो जाए तो धान की पैदावार इतनी अच्छी होगी कि कुत्ते भी भात खाने से ऊब जाएंगे और नहीं खाएंगे।

आसाढ़ी पूनो दिना, गाज बीजु बरसंत।
नासे लच्छन काल का, आनंद मानो सता।।
आषाढ़ की पूणिमा को यदि बादल गरजे, बिजली चमके और पानी बरसे तो वह वर्ष बहुत सुखद बीतेगा।

सर्व तपै जो रोहिनी, सर्व तपै जो मूर। परिवा तपै जो जेठ
की, उपजै सातो तूर।।
यदि रोहिणी भर तपे और मूल भी पूरा तपे तथा जेठ की प्रतिपदा तपे तो सातों प्रकार के अन्न पैदा होंगे।

आद्रा में जौ बोंवै साठी। दुःखै मारि निकारै लाठी।।
जो किसान आद्रा में धान बोता है वह दुःख को लाठी मारकर भगा देता है।

NEW INDIA ASSOCIATES

Life Insurance/LIC Credit Card

Car/Home Insurance

• Mediclaim

Property Sale, Purchase & Renting
at Delhi/NCR



LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED



RELIANCE GENERAL INSURANCE COMPANY

Narendra Singh Bisht

48, Hasanpur, I.P. Extension, Delhi-110092

Phone: 011-49404552, 22240184

Mobile: 9810369331, 9717494411

E-mail: anjal2006@gmail.com

HYTHRO ENGINEERS PVT. LTD

हाइथ्रो इंजीनियर्स प्रा. लि.

SUPREME ADVERTISING PVT. LTD.

सुप्रीम एडवरटाइजिंग प्रा. लि.

HANCRAFT EXPO DESIGNS PVT. LTD.

हेंनक्राफ्ट एक्सपो डिजाइंस प्रा. लि.



G. S. RAWAT

B.Sc. Engg. DCE, MIE
Chairman & Managing Director

302-303, Bhikaji Cama Bhawan
11, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066
Phone: 011-26186038, 26180238
hythroengineers@airtelmail.in
supremeadvertising@airtelmail.in



भारत में सबसे बड़े व सर्वाधिक
विश्वसनीय बीज आपूर्तिकर्ता के रूप में



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

की प्रसिद्धि का कारण है

गुणवत्ता

एनएससी के बीज अनुभववी एवं तकनीकी विशेषज्ञों की देख-रेख में कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जलवायु वाले क्षेत्रों में पैदा किए जाते हैं। बुवाई से कटाई तक तथा संसाधन से छटाई और पैकिंग तक प्रत्येक स्तर पर इन बीजों की वैज्ञानिक ढंग से देख-रेख की जाती है और इनकी गुणवत्ता की जांच की जाती है।

परीक्षण के बाद इन बीजों को सुविधाजनक आकार की थैलियों तथा पैकेटों में बन्द करके उसके ऊपर एनएससी के लेबल व प्रमाणीकरण टैग लगाकर सीलबन्द किया जाता है।

इन नाजुक बीजों की सुरक्षा के लिए इन्हें नमी नियंत्रित वातानुकूलित गोदामों में रखा जाता है।

एनएससी बीजों के भण्डारण एवं परिवहन में अत्याधुनिक पद्धतियां अपनाई जाती हैं ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की क्षति न पहुँचे तथा वे जीवन्त और तरोताजा हालत में ग्राहक के पास पहुँचें।

अपनी गुणवत्ता के बलबूते पर एनएससी आज न केवल देश के किसानों की बीज की मांग पूरी कर रहा है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी निर्यात करके अपनी साख बना रहा है।

खाद्यान्न, सब्जियों, रेशे वाली फसलों, चारे वाली फसलों, तिलहनों एवं दलहनों की सुधरी हुई अपार किस्मों के बीजों की नियमित आपूर्ति का एनएससी आपको आश्वासन दिलाता है।

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम-"मिनी रत्न" कम्पनी)

सीआईएन : यू. 74899 डीएल 1963 जीओआई 003913

(आईएसओ 9001:2015 एवं 14001:2015 प्रमाणित कम्पनी)

बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली-110012 दूरभाष/Phone : 011-25846292, 25846295

ई-मेल/E-mail : nsc@indiaseeds.com ; वेबसाईट/Website : nsc@indiaseeds.com

